लखनऊ

शनिवार, 18 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 | अंक: 234

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

# आर्यावर्त क्रांति

"मन में इच्छा, दिल में हिम्मत और कदमों में निरंतरता ये तीन चीजें हर दिन को सफल बना देती हैं।"

TODAY WEATHER

DAY 28° Hi

NIGHT 17° Low

## संक्षेप

### अब विदेशों से भी चंदा ले सकेगी धीरेंद्र शास्त्री की संस्था, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया है। इसके बाद अब यह संस्था विदेशों से मिलने वाले चंदे को कानूनी रूप से स्वीकार कर सकेगी। यह संस्था पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में काम करती है, जो देशभर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। अब तक इस संस्था को विदेशी फंड लेने की अनुमति नहीं थी लेकिन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद इसके लिए रास्ता खुल गया है। दरअसल, भारत में कोई भी एनजीओ या धार्मिक-सामाजिक संस्था अगर विदेश से पैसा लेना चाहती है, तो उसे पहले सरकार से एफसीआरए की अनुमति लेनी होती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। अनुमति मिलने के बाद ही कोई संस्था सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए विदेशी दान ले सकती है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को अब कई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसमें धार्मिक (हिंदू), सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब संस्था इन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती है।

### 'रोमांस होता तो अब तक बच्चे हो गए होते' चिराग पासवान संग अफेयर की खबरों पर बोली कंगना रनौत

नई दिल्ली। बॉलीवुड की 'क्वीन' और भारतीय जनता पार्टी की तेजतर्रार सांसद कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ अपने रिश्तों को लेकर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर खुलकर विराम लगा दिया है। कंगना ने चिराग के साथ अफेयर की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए ऐसा मजेदार जवाब दिया, जिसकी हर तरफ भारी चर्चा हो रही है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसा। संसद भवन के बाहर और अंदर चिराग पासवान के साथ अपनी बॉन्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज पर बात करते हुए कंगना ने साफ किया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह चिराग को पिछले दस सालों से जानती हैं और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफेयर की खबरों को नकारते हुए कंगना ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उनके बीच कोई रोमांस होता, तो अब तक उनके बच्चे भी हो गए होते। कंगना के इस बेबाक जवाब ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी गॉसिप्स की हवा निकाल दी है। इस इंटरव्यू के दौरान जब राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया, तो कंगना ने अपने चिर-परिचित अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह राहुल गांधी के सिर पर बेवजह ऐसा कोई 'ताज' नहीं पहना सकतीं, जिसके वह असल में हकदार ही नहीं हैं। वहीं, दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री

# महिला आरक्षण: 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, पक्ष में 298 और विरोध में पड़े 230 वोट

**नई दिल्ली, एजेंसी।** महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पर सदन में चर्चा हुई। उसके बाद 131वें संविधान संशोधन पर चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि प्रश्न यह था कि संशोधन पर विचार किया जाए। हां के पक्ष में 298 और ना के पक्ष में 230 वोट पड़े। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित नहीं हुआ। इस तरह से 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हुआ। इसके साथ ही संसदीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐलान किया कि और

दो बिल पर सदन में आगे चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को अधिकार देकर रहेगी। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करने का ऐलान किया। इस तरह से महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में पारित नहीं हो गया। बिल के पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इस दौरान लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। चूंकि यह संविधानिक विधेयक था, इसलिए विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी। सदन में 528 सांसद उपस्थित थे। इस हिसाब से दो तिहाई 326 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने की वजह से यह विधेयक पास 28 वोट से गिर गया। 11 सालों के मोदी सरकार के शासन में यह पहला मौका जब सरकार सदन में कोई विधेयक पारित नहीं करवा पाई। इससे पहले चर्चा पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष का आरोप लगाया कि विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर विपक्ष वोट नहीं देगा तो यह विधेयक गिर जाएगा, लेकिन देश की महिलाओं को पता चल जाएगा कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है। देश की महिलाएं देख रही है कि कौन महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। इन संशोधित विधेयकों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई। चर्चा में कुल 130 सांसदों ने हिस्सा लिया और इनमें 56 महिला सांसद थीं।

### अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना

अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं और न देश के हित में है।

### देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश

वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस विधेयक को 'संविधान पर हमला' बताते हुए कहा कि यह देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी।

### स्वर्ग तो छोड़िए, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा

उन्होंने जोर देकर कहा, "ऐसे मुखिया को भी आप भूल जाएंगी, तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, स्वर्ग की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने सरकार की 'बेटी बचाओ' जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज हर घर में सरकार की योजनाओं का प्रमाण मौजूद है, प्रदेश के अभिभावक के रूप में मुखिया हर आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, चुनाव में किसी के बहकावे में आना गलत होगा। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।

## संसद में राहुल के बयान पर हंगामा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- देश से माफी मांगें, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र

**नई दिल्ली, एजेंसी।** लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। राहुल के बयान पर सत्ताधारी दल के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में शोर-शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। उन्होंने सरकार से 2023 के महिला आरक्षण विधेयक को दोबारा लाने की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष इसे तुरंत लागू कराने में पूरा सहयोग देगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सत्ता और प्रतिनिधित्व देने से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा

कि यही सरकार की वास्तविक मंशा प्रतीत होती है।

### 'छिपी ताकत' वाले बयान पर हंगामा

राहुल गांधी ने कहा, 'मैं वापस गार्डन वाली कहानी सुनाता हूं। दादी ने कहा था कि सुनो राहुल मैं चाहती हूं कि तुम अंधेरे में देखना सीखो। अंधेरा में ही असली ताकत है। यह बढ़िया पॉलिटिकल लेशन है। जो असली ताकत होती है वो छिप कर काम करती है अपने आप को दिखाती नहीं है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि सभी जानते हैं एक पार्टनरशिप हमारे जादूगर और बिजनेसमैन के बीच है।' इस पर एनडीए सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल ने कहा- मैं पीएम का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने पीएम का नाम नहीं लिया। सर यह पार्टनरशिप मजबूत है, लेकिन छिपी है। जादूगर के पूरे इतिहास में यह ताकत छिपी है। जबसे वे यहां आए तब से यह चल रहा है।

राजनाथ बोले- ये देश का अपमान

राहुल के जादूगर शब्द पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आपत्ति जताई है। कहा- 'विपक्ष के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। पीएम के लिए ऐसा बोलेंगे। वे चुने हुए लीडर हैं।' राजनाथ बोले- 'इस देश के पीएम के संबंध में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। इस देश की जनता ने उन्हें पीएम बनाया है। राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाए और राहुल माफी मांगे।'

## संसद में महिला आरक्षण पर बहस : विपक्ष ने सरकार को घेरा, टीएमसी और सपा ने सत्ता पक्ष से पूछे तीखे सवाल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर शुक्रवार को जोरदार चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी शक्ति' की बात करती है, उसे पहले अपने संगठन के भीतर महिलाओं को उचित स्थान और सम्मान देना चाहिए। कल्याण बनर्जी ने सदन में आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भाजपा के 242 लोकसभा सांसदों में केवल 41 महिलाएं हैं। इसी तरह राज्यसभा में भाजपा के 106 सदस्यों में से सिर्फ 18 महिला सांसद हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा सच में महिला सशक्तीकरण चाहती है, तो उसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं

को देने चाहिए। परिसीमन को लेकर भी कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर महिला आरक्षण देना है, तो इसे तुरंत लागू किया जाए और इसके लिए परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे नौटंकी बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ लोगों को बरगला रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा, आप लोग सिर्फ 'जय श्रीराम' कहते हैं, लेकिन हम दुर्गा और काली की पूजा करते हैं। हम 'जय सिया राम' कहते हैं, क्योंकि राम बिना सीता के अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान उनकी संस्कृति का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान बताया और सुझाव दिया कि स्पीकर के पद पर भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए।

### हसीना के प्रत्यर्पण का मामला

## कानूनी प्रक्रिया जारी, नई सरकार के साथ रिश्तों पर रहेगा जोर : रणधीर जायसवाल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच, भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उनके प्रत्यर्पण से जुड़ी एक याचिका पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी याचिका की समीक्षा की जा रही है। यह हमारी न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है।'

उन्होंने कहा, 'हम इस मामले में सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेंगे और मौजूदा घटनाक्रमों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है।' MEA प्रवक्ता ने बताया कि विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव की इच्छा जताई है। भारत का लक्ष्य पड़ोसी देश के साथ आपसी रिश्तों की गहराई को और बढ़ाना है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि प्रासंगिक द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से इस साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रस्तावों पर काम किया जाएगा।

## सबरीमाला मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- व्यक्तिगत मान्यताओं से ऊपर है संविधान की मर्यादा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आस्था और परंपराएं न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। सबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जजों को किसी भी मामले पर फैसला सुनाते समय अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं को किनारे रखकर केवल 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' और 'सांविधानिक ढांचे' का पालन करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान उन बुनियादी सवालों को कुरेदा, जो धर्म और संविधान के टकराव के बीच अक्सर खड़े होते हैं। वहीं, अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि यह लड़ाई सिर्फ एक मंदिर या एक समुदाय की नहीं है, बल्कि यह उन तमाम विश्वासों की है जो संविधानिक दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय का काम समाज में विभाजन को रोकना और सामंजस्य स्थापित करना है, बशर्ते धर्म पर उठाए जाने वाले सवाल सम्मानजनक हों।

### सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एक गंभीर बिंदु उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक जज के तौर पर हम धर्म और अंतरात्मा को एक ही तराजू पर तौल सकते हैं? उनका मानना था कि भले ही धर्म एक व्यक्तिगत विषय हो, लेकिन जब न्यायिक फैसले की बारी आती है, तो एक जज को उस धार्मिक चेतना से ऊपर उठकर व्यापक सांविधानिक परिप्रेक्ष्य और संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 'अंतरात्मा' और 'धर्म' के अंतर्संबंधों पर अधिवक्ता से तीखे सवाल किए। जवाब में राजीव धवन ने एक व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि यदि हर धार्मिक अनुष्ठान को तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा, तो धर्म का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है।

## 48 दिन बाद खुला होर्मुज : व्यापारिक जहाजों को आने-जाने की मिली छूट, ईरान ने किया एलान, ट्रंप ने कहा- शुक्रिया

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और 48 दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद आखिरकार होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान ने घोषणा की है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से अब व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली रहेगी और उन्हें आने-जाने की पूर्ण छूट दी गई है। यह कदम लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद उठाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान में सीजफायर समझौते के अनुरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह खोल दिया गया है। विदेश मंत्री के अनुसार, यह निर्णय सीजफायर अवधि के शेष समय के लिए लागू रहेगा और पहले से घोषित समन्वित मार्ग के तहत सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया है।

### ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि 'ईरान ने अभी घोषणा की है कि ईरान का जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और पूरी तरह से गुजरने के लिए तैयार है। धन्यवाद!'

### वैश्विक व्यापार के लिए अहम कदम

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग को खोलने का निर्णय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग के लिए राहत भरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को कम करने और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

### ईरान से निकल रहे 13 जहाजों को अमेरिका ने लौटाया

अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है।

### ईरान युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी संसद में खारिज

गौरतलब है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को सदन ने बृहस्पतिवार को एक वोट से खारिज कर दिया। प्रस्ताव के विरोध में 214 और समर्थन में 213 वोट पड़े।

## अब विदेशों से भी चंदा ले सकेगी धीरेंद्र शास्त्री की संस्था, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया है। इसके बाद अब यह संस्था विदेशों से मिलने वाले चंदे को कानूनी रूप से स्वीकार कर सकेगी। यह संस्था पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में काम करती है, जो देशभर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। अब तक इस संस्था को विदेशी फंड लेने की अनुमति नहीं थी लेकिन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद इसके लिए रास्ता खुल गया है। दरअसल, भारत में कोई भी एनजीओ या धार्मिक-सामाजिक संस्था अगर विदेश से पैसा लेना चाहती है, तो उसे पहले सरकार से एफसीआरए की अनुमति लेनी होती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो और उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। अनुमति मिलने के बाद ही कोई संस्था सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए विदेशी दान ले सकती है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को अब कई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन मिला है, जिसमें धार्मिक (हिंदू), सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब संस्था इन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती है।

# अतीक व गुर्गों से खाली कराई गई जमीन पर शहरियों को मिलेंगे सस्ते घर, पीडीए ने शासन को भेजा पत्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**प्रयागराज।** अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरियों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमाफिया के अवैध कब्जे से खाली कराए जाने के बाद कुर्क की गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है।

पीडीए की ओर से शासन को पत्र भेजकर तहसील सदर के कटहुआ गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर यानी 55,100 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। सूत्रों के अनुसार पीडीए की ओर से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि न्यायालय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, प्रयागराज ने कटहुला गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर भूमि को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी व क्रियाकलाप निवारण अधिनिय, 1986 के तहत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया था।

### गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य में निहित हो गई हैं अतीक की संपत्तियां

इसी क्रम में प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अतीक अहमद व अन्य में 16 जुलाई 2024 को कुर्क संपत्तियों को राज्य में निहित कर दिया था। पत्र के जरिये कहा गया है कि विभिन्न जनपदों में भूमाफिया से खाली कराई गईं जमीनों को जनोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाना है। पीडीए द्वारा भूमाफिया से खाली कराई गई जमीनों का नियमानुसार नियोजन एवं विकास कर आवासीय समस्याओं के निराकरण में सहयोग किया जा सकता है।

पीडीए ने पत्र के साथ माफिया और कुर्क संपत्तियों की सूची भी प्रमुख सचिव को भेजी है और उनसे अनुरोध किया है कि भूमाफिया से रिक्त कराई गई एवं राज्य में निहित तकरीबन 5.510 हेक्टेयर जमीन जनोपयोगी कार्य के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए। पीडीए की ओर से कुल 16 संपत्तियों की सूची और प्रत्येक संपत्ति पर दर्ज आराजीदारों के नाम शासन को उपलब्ध कराए गए हैं।

### कालिंदीपुरम में 100 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा चिह्नित

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कालिंदीपुरम में अपनी जमीन पर भूमाफिया के अवैध कब्जे को चिह्नित किया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये है। इस मामले में पीडीए के उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के अवर अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है और मौके पर निगरानी के लिए तैनात किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। इस जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा।

### एयरपोर्ट के आसपास बढ़ाई गई निगरानी

पीडीए सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट के आसपास जमीनों पर अवैध कब्जे की निगरानी बढ़ा दी गई है। पीडीए वहां तकरीबन 28 हेक्टेयर जमीन पर एक बड़ी टाउनशिप बसाने की तैयारी कर रहा है। इस टाउनशिप के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण में कटहुला गौसपुर गांव का वह हिस्सा भी शामिल है, जहां भूमाफिया से खाली कराई गई जमीन राज्य में निहित की जा चुकी है। एयरपोर्ट के आसपास के अन्य इलाकों में भी भूमाफिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध कब्जों को चिह्नित किया जा रहा है।

# दो शटर के बीच फलता-फूलता चमत्कारी अस्पताल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**सुल्तानपुर।** शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अनोखा नमूना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दो शटरों के बीच संचालित हो रहा एक तथाकथित अस्पताल न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहा है बल्कि नियम-कानूनों को भी आईसीयू में भर्ती कर चुका है।

बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में डॉ. मो. नदीम खान और डॉ. अबसार अहमद का नाम तो बड़े गर्व से लिया जाता है जबकि दोनों ही चिकित्सकों ने यहां अपनी सेवाएं देने से साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर ही नहीं हैं तो इलाज कौन कर रहा है या फिर इलाज के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। उधर डॉ. बुशरा अंजुम को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताया जाता है लेकिन उनकी डिग्री किस अलमारी में बंद है या किस फाइल में दब गई है इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नजर नहीं आता। शायद यह भी गोपनीय श्रेणी में आता हो। इस पूरे खेल के केंद्र में हैं डॉक्टर हैदर जो खुद को डॉक्टर लिखने वाले हैदर साहब। जिनका अतीत जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए पुरुष स्टाफ नर्स के रूप में कुछ समय बिताने का रहा है। आरोपों की फेहरिस्त इतनी लंबी बताई जाती है कि अंततः उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन जनाब का हौसला देखिए अब खुद ही अस्पताल चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प पहलू है उनकी डिग्री बीईएमएस जिसे एसीएमओ/नोडल अधिकारी डॉ. जे.सी. सरोज द्वारा फर्जी बताया जा चुका है। इसके बावजूद हैदर साहब का डॉक्टरी आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ।

अब असली सवाल यही है कि आखिर यह सब कैसे चल रहा है? क्या यह सिर्फ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा खेल है या फिर ऊपर तक इसकी जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदी जा रही हैं। चर्चा है कि बिना किसी संरक्षण के इस तरह का संचालन संभव ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी ही इस अस्पताल की सबसे बड़ी दवा बन गई है। फिलहाल सब सोचने पर मजबूर है कि इलाज कराने जाएं या सिस्टम के इस चमत्कार को देखने। क्योंकि यहां बीमारी से ज्यादा गंभीर स्थिति नियमों और जिम्मेदारियों की नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को भी रूटीन जांच में डालकर ठंडे बस्ते में भेजते हैं या फिर कभी इन दो शटरों के बीच छिपे सच पर भी ताला टूटेगा।

# पुलिस लाइन में सख्त अनुशासन की झलक

आर्यावर्त संवाददाता

**सुल्तानपुर।** पुलिस लाइन्स सुलतानपुर में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड उस वक्त खास बन गई, जब पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने स्वयं पहुंचकर परेड की सलामी ली और तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी ने परेड ग्राउंड पर मौजूद पुलिसकर्मियों के वर्दी टर्नआउट, शस्त्रों की स्थिति और समग्र प्रस्तुति को गंभीरता से परखा। अनुशासन को पुलिस बल की रीढ़ बताते हुए उन्होंने टोलीवार ड्रिल का निरीक्षण किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों की खुलकर सराहना की गई, वहीं कमियों पर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए। पासिंग आउट परेड को लेकर एसपी का रुख बेहद स्पष्ट रहा। उन्होंने प्रशिक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिक्रूट आरक्षियों को हर गतिविधि में पूरी तरह दक्ष बनाया जाए, ताकि परेड में पुलिस बल की पेशेवर छवि पूरी मजबूती से उभरकर सामने आए। रिक्रूट आरक्षियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पासिंग आउट परेड केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पुलिस की क्षमता, अनुशासन और प्रतिबद्धता का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद एसपी ने क्वार्टर गार्ड में सलामी ली और अर्दली रूम में अभिलेखों का अवलोकन किया। रजिस्टरों के नियमित अपडेट, परिसर की साफ-सफाई और सुव्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर पुलिस लाइन में शुक्रवार का दिन अनुशासन, सजगता और सख्त संदेश के नाम रहा, जहां हर कदम पर व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश साफ नजर आई।

# चौकी के बाहर महिलाओं में मारपीट, सड़क पर खींचे एक-दूजे के बाल, पुलिस ने संभाला मामला

आर्यावर्त संवाददाता

**मुजफ्फरनगर।** मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन को लेकर बृहस्पतिवार को बघरा पुलिस चौकी के बाहर दो परिवारों की महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाएं एक-दूसरे के बाल पकड़कर सड़क पर ही भिड़ गईं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह स्थिति को काबू में लिया।

### पुराने विवाद से शुरू हुआ झगड़ा

जानकारी के अनुसार सैदपुरा खुर्द निवासी छोटू उर्फ सचिन और धर्मा के साथी करीब दो वर्ष पहले कर्नाटक में कोल्हू पर काम करने गए थे। वहां से लौटने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें छोटू को चोट भी आई थी।

### पांच हजार रुपये का था विवाद

बाद में गांव के लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था और धर्मा की ओर से पांच हजार रुपये दिए गए थे। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को इसी रकम को लेकर दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई।

### चौकी के बाहर फिर भड़का विवाद

सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और छोटू उर्फ सचिन तथा दूसरे पक्ष से सोनू को अपने साथ चौकी ले आई। इसी दौरान दोनों परिवारों की महिलाएं भी बघरा पुलिस चौकी पहुंच गईं। चौकी के बाहर ही दोनों पक्षों में फिर से गाली-गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते महिलाएं आपस में भिड़ गईं। शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई।

### पुलिस ने शांत कराया मामला, जांच जारी

मामला बढ़ता देख चौकी से पुलिसकर्मी बाहर आए और काफी मशक्कत के बाद महिलाओं को अलग कराया। इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस ने बताया कि सचिन और सोनू को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

# बजरंग दल-विहिप ने धर्मांतरण पर सख्त कानून की मांग की, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

आर्यावर्त संवाददाता

**सुल्तानपुर।** विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने अवैध धर्मांतरण और तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी कठोर कानून बनाने की मांग की है।

बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील राष्ट्रवादी जी ने कहा कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) नासिक से जुड़े मामले के सामने आने के बाद यह मुद्दा गंभीर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियां केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टेक महिंद्रा जैसी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक भी फैली हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवाओं के माध्यम से धर्मांतरण के प्रयासों की खबरें चिंताजनक हैं और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। विहिप ने उन महिला पुलिसकर्मियों की सराहना की, जिन्होंने कथित रूप से मामले का खुलासा करने में भूमिका निभाई। विहिप नेताओं ने दावा किया कि इस प्रकार की घटनाएं देश की सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में बने सख्त कानूनों से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगा है, इसलिए पूरे देश में एक समान और प्रभावी कानून लागू किया जाना चाहिए। संगठन ने यह भी मांग की कि मामले की जांच राष्ट्रीय स्तर पर की जाए और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी एजेंसियों को शामिल किया जाए।

इस संबंध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा। इस अवसर पर बजरंग दल प्रांत संयोजक सुशील राष्ट्रवादी, विभाग संयोजक गौरव पांडेय, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर जिला संयोजक प्रांजल सिंह, जिला सहसंयोजक यशदीप ठठेर, मोतिगरपुर प्रखंड संयोजक अनमोल अग्रहरि, जयसिंहपुर प्रखंड संयोजक अमन जायसवाल, गिरीश मिश्रा, सत्यम अग्रहरि, सूरज अग्रहरि, रमेश मोदनवाल, विहिप प्रांत कार्यकारिणी सदस्य राम मनोहर एवं रामेश्वर सिंह, सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विहिप और बजरंग दल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की दिशा में कदम उठाएं।

### जजों के ट्रांसफर से प्रभावित मजिस्ट्रेट अदालतों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

**सुलतानपुर।** हाईकोर्ट के निर्देशन में हुए जजों के वार्षिक ट्रांसफर के मद्देनजर एवं जिला जज सुनील कुमार के निर्देशन में कई जजों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देशन में स्थानांतरित होकर आए सेशन जजों को उनकी नई तैनाती बुधवार को ही सौंप दी गई। वहीं जिला जज सुनील कुमार व सीजेएम नवनीत सिंह के निर्देशन में मजिस्ट्रेट अदालतों के कार्यक्षेत्र में बृहस्पतिवार को बदलाव किया गया है। जिसके क्रम में स्थानांतरित होकर आई न्यायिक अधिकारी तुबा फातिमा को अपर सिविल जज-जूनियर डिवीजन कोर्ट नम्बर- 26 का प्रभार सौंपा गया है,जिन्हें रिक्त हुई एसीजेएम कोर्ट नम्बर-20 से कूरेभार थाना हटाकर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सौंपा गया है। वहीं एसीजेएम कोर्ट नम्बर-20 पर तैनात रही न्यायिक अधिकारी भव्या श्रीवास्तव को स्थानांतरित हुई अनुजया कृष्णा के स्थान पर सिविल जज-सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की जिम्मेदारी मिली है।

# गर्मी के बीच मौसम लेगा यूटर्न... दिल्ली-बिहार और राजस्थान में बारिश, यूपी में बढ़ेगा पारा; पहाड़ों का क्या है हाल?

आर्यावर्त संवाददाता

**ग्रेटर नोएडा।** दिल्ली-एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अभी पारा और बढ़ने की संभावना जताई है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है।

आईएमडी के अनुसार देशभर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। एक तरफ कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में लू और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम यू-टर्न लेगा और आज हल्की बारिश की संभावन है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। बुधवार को बांदा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया था। IMD के अनुसार राज्य में दो से तीन दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकती है और हल्की बारिश के आसार हैं।

### बिहार में होगी बारिश

मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में आज और कल हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 19 अप्रैल से फिर गर्मी बढ़ेगी और इस दौरान लू चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होगी।

### हिमाचल-उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 19 अप्रैल के बीच बारिश और बर्फबारी के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 17 अप्रैल को हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।

### एमपी में लू चलने का अलर्ट, राजस्थान में बारिश

एमपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। एमपी में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लूट चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज जयपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

# नोएडा ने लगाई 'हाफ सेंचुरी'... 50 साल में गांव से ग्लोबल हब बना

आर्यावर्त संवाददाता

**ग्रेटर नोएडा।** आज का आधुनिक और चमकता-दमकता 'नोएडा' कभी बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता था। यहां दूर-दूर तक फैले खेत, कच्ची सड़कें, धूल के गुबार और छोटे-छोटे गांव ही इसकी पहचान थे। यमुना और हिंडन नदियों के बीच बसा यह इलाका पूरी तरह ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ था। यहां के लोगों की जिंदगी खेती और पारंपरिक कामों पर निर्भर थी। 17 अप्रैल 1976 को जब नोएडा की स्थापना हुई, तब यह सिर्फ एक योजना थी। दिल्ली के बढ़ते दबाव को कम करने और उद्योगों को एक व्यवस्थित जगह देने थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह उबड़-खाबड़ जमीन एक दिन देश के सबसे विकसित और हाईटेक शहरों में शामिल हो जाएगी। नोएडा के विकास की शुरुआत औद्योगिक शहर के रूप में हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कई

छोटे-बड़े उद्योगों को यहां शिफ्ट किया गया। योजनाबद्ध तरीके से सेक्टर बनाए गए, जहां उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों को अलग-अलग रखा गया। इस दौरान सड़कें बनीं, बिजली और पानी की सुविधाएं विकसित की गईं। धीरे-धीरे लोगों का आना शुरू हुआ। हालांकि यह विकास शुरुआती स्तर का था और शहर अब भी सीमित दायरे में ही था। फिर भी यही वह समय था, जिसने नोएडा की नींव को मजबूत किया और आगे आने वाले विकास की दिशा तय की गई।

1990 के दशक में नोएडा ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि रिहायशी शहर के रूप में भी उभरने लगा। हाउसिंग सोसाइटियां बनने लगीं। अपार्टमेंट संस्कृति आई और लोगों ने इसे रहने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। इस समय तक नोएडा में स्कूल, अस्पताल और बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित होने लगी थीं। हालांकि कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मजबूत नहीं था, लेकिन शहर धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहा था।

### तीसरा दौर- साल 2000 के बाद आई असली रफ्तार

नोएडा के विकास की असली कहानी साल 2000 के बाद शुरू होती है। इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर काम हुआ। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, बेहतर सड़क नेटवर्क और दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी ने शहर को नई दिशा दी। आईटी सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से नोएडा तेजी से रोजगार का केंद्र बन गया। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने यहां अपने ऑफिस खोले, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला और शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। यही वह समय था, जब नोएडा ने हाईटेक सिटी की पहचान बनानी शुरू की और देश-विदेश के निवेशकों का ध्यान अपनी और खींचा।

### गुरुग्राम की तर्ज पर विकास, लेकिन सीमित दायरे की चुनौती

नोएडा का विकास काफी हद तक गुरुग्राम की तर्ज पर किया गया। यहां भी कॉरपोरेट ऑफिस, आईटी पार्क, चौड़ी सड़कें और आधुनिक इमारतें बनाई गईं। इसके साथ ही नोएडा में कई बड़े मॉल बनाए गए, जो कि नोएडा शहर को अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए, लेकिन एक बड़ा अंतर यह रहा कि प्रोग्राम लगातार फैलता गया, जबकि नोएडा एक सीमित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। जमीन और योजना की सीमाओं के कारण इसका विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पाया, जितनी जरूरत थी। यही वजह रही कि सरकार को एक नए शहर ग्रेटर नोएडा की जरूरत महसूस हुई, ताकि विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके।

### 'ग्रेटर नोएडा'- अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश

नोएडा की सीमाओं और बढ़ती आबादी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा का विकास किया गया। यहां ज्यादा चौड़ी सड़कें, बेहतर प्लानिंग और बड़े प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जगह दी गई। ग्रेटर नोएडा में उन सुविधाओं को शामिल करने की कोशिश की गई, जो नोएडा में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए। इससे दोनों शहरों का संतुलित विकास संभव हुआ और क्षेत्र को एक बड़े शहरी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया।

नोएडा की सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक इसकी जमीन की कीमतों में हुई। जमीन की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जहां शुरुआत में जमीन बेहद सस्ती थीं, वहीं आज यहां लाखों और करोड़ों रुपए में बिक रही हैं। पिछले कुछ दशकों में प्रॉपर्टी के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। निवेश के लिहाज से नोएडा आज देश के सबसे आकर्षक शहरों में शामिल है। यह उछाल इस बात का संकेत है कि नोएडा ने आर्थिक रूप से कितनी मजबूत स्थिति हासिल कर ली है।

### आज का नोएडा हाईटेक, कनेक्टेड और निवेश का केंद्र

आज नोएडा एक पूरी तरह आधुनिक शहर बन चुका है। यहां मेट्रो, एक्सप्रेस-वे, बड़े मॉल, अस्पताल, स्कूल और कॉरपोरेट ऑफिस... जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेट्रो विस्तार और अन्य बड़े प्रोजेक्ट इस शहर को और आगे ले जाने वाले हैं। यह शहर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का एक प्रमुख आईटी और आर्थिक हब बन चुका है।

### विकास के बीच रह गईं कुछ अहम कमियां

तेजी से हुए विकास के बावजूद नोएडा में कई समस्याएं आज भी लोगों को परेशान करती हैं। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हरियाली की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। योजनाबद्ध तरीके से शहर होने के बावजूद कई क्षेत्रों में ग्रीन स्पेस उतना विकसित नहीं हो पाया, जितनी उम्मीद थी। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या बार-बार सामने आती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। सीवर और ड्रोनेज सिस्टम भी कई जगहों पर कमजोर है, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा प्रदूषण और अनुयोजित शहरी विस्तार भी धीरे-धीरे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

### 1000 करोड़ के नए प्रोजेक्टस से बढ़ेगी रफ्तार

नोएडा अपने 50वें स्थापना दिवस पर करीब 1000 करोड रुपए की नई परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। इससे न केवल शहर को और तेजी से विकास मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में लोगों को और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं आने वाले समय में नोएडा शहर को एक अलग पहचान देंगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे।

# गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दो आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन, सुरक्षा को बताया सुशासन की पहली शर्त

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त है और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आरक्षी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक जैसे कार्मिक समाज के बीच से ही आते हैं और जब वे भर्ती एवं प्रशिक्षण के बाद पुलिस विभाग में कार्य प्रारम्भ करते हैं, तो उनके लिए उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।मुख्यमंत्री गोरखपुर जनपद में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 9.18 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, पुलिस भंडार कक्ष तथा अनुरक्षण कार्यशाला सहित दो आधुनिक सुरक्षा भवनों का उद्घाटन करने के उपरांत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के समीप निर्मित यह सुरक्षा भवन एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। पूर्व में सुरक्षाकर्मियों को ठहरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पुलिसकर्मियों, सामान्य अतिथियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यही मॉडल सुशासन और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस भवन में लगभग 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक साथ ठहर सकेंगे। साथ ही यहां पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक और अन्य सुरक्षाबलों के लिए आवासीय सुविधा, भोजनालय, कार्यालय और बैठक कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले नौ वर्षों में दो लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती पूरी की है। वर्ष 2017 से पहले पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त रहते थे और प्रशिक्षण की क्षमता एक समय में तीन हजार से अधिक नहीं थी। वर्तमान में पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के विकास के कारण एक साथ 60 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो समय पर लिए गए निर्णयों और संसाधनों के विस्तार का परिणाम है।उन्होंने कहा कि पहले थाना, चौकी, पुलिस लाइन और पीएसी वाहिनियों में पुलिस कार्मिकों के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिसके कारण उन्हें किराये के मकानों में रहना पड़ता था। अब प्रत्येक पुलिस लाइन में लगभग 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की गई हैं तथा महिला और पुरुष पुलिस कार्मिकों के लिए अलग-अलग बैरकों का निर्माण कराया गया है।

# गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, "घबराइए मत, सरकार आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी।"शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री करीब 200 लोगों से मिले। उन्होंने लोगों के पास जाकर उनकी बातें सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उनका अवलोकन किया। इसके बाद विभिन्न मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक ढंग से किया जाए। जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरतमंद मरीजों के उच्च स्तरीय इलाज का खर्च का अनुमान शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो पात्र लोग अभी तक पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिलाया जाए।

# मधुबन में नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय भवन का उद्घाटन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणा

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ जनपद के भ्रमण के दौरान आदर्श नगर पंचायत मधुबन के नवनिर्मित कार्यालय भवन का देर शाम उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।अपने संबोधन में मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मात्र 65 लाख रुपये की लागत से इस कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है। कम लागत में बेहतर गुणवत्ता का निर्माण कार्य होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें और अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।मंत्री ने कहा कि मधुबन क्षेत्र की सभी सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा तथा सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी।उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यदि मधुबन क्षेत्र की तस्वीर बदलनी है तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इसी दिशा में उन्होंने किसान बाजार, कृषि मंडी, शीतगृह तथा मिनी शीतगृह स्थापित करने की घोषणा की, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों।मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि लगभग 25 से 30 वर्षों से बंद पड़ी परदहा मिल, जहां भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, वहां शीघ्र ही औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र को औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे मधुबन क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कृषि और उद्योग के समन्वय के माध्यम से मधुबन क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा और आने वाले समय में यह क्षेत्र प्रगति की नई मिसाल बनेगा।

# कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को गौतमबुद्धनगर जाने से रोका गया, पुलिस कार्रवाई पर जताई कड़ी आपत्ति

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिए गए कथित गलत बयान के विरोध में प्रदर्शन के दौरान नोएडा पुलिस के रवैये में जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष दीपक चोटीवाला घायल हो गए थे। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय उनका कुशलक्षेम जानने उनके आवास जनपद गौतमबुद्धनगर जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ता से मिलने से रोकना बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने और जनसरोकार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है।

अजय राय ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की दमनकारी नीतियों से डरने वाली नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासन को सत्ता के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष और कानूनसम्मत तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस घटना की घोर निंदा करती है और चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई गईं, तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

## • संक्षेप •

### प्रदेश में 896 मदिरा व भांग दुकानों के आवंटन हेतु तृतीय चरण ई-लॉटरी के आवेदन शुरू

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की ई-नवीनीकरण तथा द्वितीय चरण ई-लॉटरी के बाद अवशेष एवं नवसृजित कुल 896 फुटकर दुकानों के आवंटन के लिए तृतीय चरण की ई-लॉटरी प्रक्रिया हेतु आवेदन आज से प्रारंभ कर दिए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।आबकारी विभाग द्वारा जारी नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश भर की मदिरा दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सुगमता सुनिश्चित हो सके। इच्छुक आवेदक निर्धारित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। आवश्यक शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। सभी आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि आवेदन करने से पूर्व नियमों एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें।

### हज यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर हज हाउस में समीक्षा बैठक, व्यवस्थाओं का किया गया निरीक्षण

**लखनऊ।** हज यात्रा 2026 की तैयारियों के दृष्टिगत आज हज हाउस, लखनऊ में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।बैठक के दौरान मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने हज यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि हज पर जाने वाले सभी अकीदतमंदों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं।मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हज यात्रा की तैयारियां समयबद्ध, सुव्यवस्थित और संवेदनशीलता के साथ पूर्ण की जाएं, जिससे प्रत्येक यात्री अपनी पवित्र यात्रा सुरक्षित और सहज रूप से संपन्न कर सके।बैठक में राज्य हज समिति के सदस्यगण, हज सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

### नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद

**लखनऊ।** पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनन्द के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज विकास कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज ब्रजेश कुमार द्वारा गठित टीम ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15 अप्रैल 2026 को शिकायतकर्ता द्वारा सूचना दी गई कि 11 अप्रैल 2026 को वह अपने परिवार के साथ एक ढाबे पर भोजन करने के बाद सो गया था। रात्रि लगभग 2 बजे नींद खुलने पर उसकी लगभग 15 वर्षीय पुत्री गायब मिली। परिजनों ने नाते-रिश्तेदारों एवं परिचितों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।इसके बाद 12 अप्रैल 2026 को एक परिचित द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम बख्तौरी खेड़ा निवासी सुभाष नामक युवक द्वारा उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा संख्या 145/26 धारा 87/137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा 16 अप्रैल 2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा आरोपी सुभाष पुत्र अमरेश रावत निवासी बख्तौरी खेड़ा थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ उम्र लगभग 20 वर्ष को उसी दिन शाम लगभग 7:20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को 17 अप्रैल 2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

# नोएडा जाने से पहले सपा प्रतिनिधिमंडल को रास्ते में रोका गया, श्रमिकों से मिलने जा रहे थे नेता

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में पीड़ित श्रमिकों से मिलने एवं उनकी समस्याओं को जानने के लिए रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल में कमाल अख्तर (विधायक/पूर्व मंत्री), सुधीर भाटी (जिलाध्यक्ष), आश्रय गुप्ता (महानगर अध्यक्ष), शाहिद मंजूर (विधायक/पूर्व मंत्री), अतुल प्रधान (विधायक), पंकज कुमार मलिक (विधायक), प्रशांत यादव (पूर्व सदस्य विधान परिषद), राज कुमार भाटी (प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी) तथा सुनील चौधरी (पूर्व प्रत्याशी, नोएडा) सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे।बताया गया कि प्रस्थान से पूर्व पुलिस प्रशासन द्वारा इन सभी नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद करने का प्रयास किया गया, किंतु सभी नेता लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने-अपने आवासों से निकलकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नोएडा के लिए रवाना हुए। हालांकि रास्ते में ही पुलिस द्वारा प्रतिनिधिमंडल को जबरन रोक दिया गया और आगे जाने से रोक दिया गया, जिसे पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत एवं निंदनीय कार्यवाही बताया है।समाजवादी पार्टी के अनुसार नोएडा क्षेत्र में श्रमिकों से 10 से 12 घंटे कार्य लिया जा रहा है, जबकि उन्हें मात्र 10 से 11 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है तथा साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जा रहा।

### हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत, छत पर झालर लगाते समय हुआ हादसा

**लखनऊ।** थाना क्षेत्र दुबग्गा के इज्जत नगर इलाके में एक युवक की 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को लगभग 2:40 बजे थाना क्षेत्र के इज्जत नगर में नोबल पब्लिक स्कूल के पीछे एक युवक के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने की सूचना प्राप्त हुई। प्रारम्भिक जांच में पता चला कि मकान मालिक साकिब अब्बास पुत्र वजीउल्लाह हसन द्वारा इज्जत नगर कॉलोनी, महीपत मऊ थाना दुबग्गा क्षेत्र में अपने नए मकान का निर्माण कराया गया था और गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी।इसी दौरान मकान की छत की रेलिंग पर झालर लगाने का कार्य मिस्त्री सुहेल पुत्र जुबेर निवासी तिलक खेड़ा थाना संडीला जनपद हरदोई, उम्र लगभग 24 वर्ष द्वारा किया जा रहा था।

# बंथरा क्षेत्र में एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

**लखनऊ।** थाना बंथरा क्षेत्र के जुनाबगंज मोहनलालगंज रोड स्थित ग्राम पहाड़पुर में बने एटीएम बूथ से तोड़फोड़ कर रुपये चोरी करने का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सब्बल, ग्राइंडर मशीन, मोटरसाइकिल, हेल्मेट तथा अन्य सामान भी बरामद किया है।पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को वादी शौर्य श्रीवास्तव निवासी ग्राम पहाड़पुर थाना बंथरा द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि के समय एटीएम बूथ में घुसकर चोरी के इरादे से एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बंथरा में मुकदमा संख्या 95/2026 धारा 324(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर 16 अप्रैल 2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे धांवापुर क्षेत्र स्थित ड्रीम ग्रीन सिटी से अभियुक्त गुलसन पुत्र मैकूलाल गौतम निवासी ग्राम सेरसा, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव (हाल पता खसरवारा, थाना बंथरा, लखनऊ) को गिरफ्तार कर लिया।अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या यूपी 32 क्यूएस 5384, हेल्मेट, काला पिट्ठू बैग, मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखी ग्राइंडर मशीन तथा घटना में प्रयुक्त सब्बल (लोहे का सरिया) बरामद किया गया।घटना के संबंध में वादी ने बताया कि उसका व्यापारिक परिसर जुनाबगंज मोहनलालगंज रोड पर स्थित है, जहां वह दुकानों को किराये पर देने के साथ एटीएम बूथ संचालित करता है। 10 अप्रैल 2026 की रात्रि लगभग 10 बजे वह एटीएम बंद कर अपने घर चला गया था। अगले दिन 11 अप्रैल को सुबह लगभग 5 बजे वापस आने पर एटीएम मशीन क्षतिग्रस्त मिली। सीसीटीवी फुटेज की जांच में 11 अप्रैल की रात्रि लगभग 2:50 बजे एक व्यक्ति हेल्मेट लगाकर एटीएम बूथ में घुसते हुए और औजारों से मशीन तोड़ते हुए दिखाई दिया।

# नारी शक्ति वंदन अधिनियम—प्रतिनिधित्व से राष्ट्रनिर्माण तक

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष

**'यत्र नार्यस्तु** पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' – यह केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि भारत की शाश्वत संस्कृति का उद्घोष रहा है। लेकिन पूजा और सम्मान से आगे बढ़कर, आज का भारत 'अधिकार', 'अस्तित्व' और 'नेतृत्व' की बात कर रहा है। *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* केवल एक वैधानिक प्रलेख नहीं है, बल्कि सदियों से बंद उन द्वारों की कुंजी है जिसके पीछे भारत की आधी आबादी का सामर्थ्य अवरुद्ध था। यह अधिनियम किसी पर किया गया उपकार नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय का परिमार्जन है जो कालचक्र ने महिलाओं के साथ किया। आज महिलाएं आरक्षण इसलिए नहीं मांग रही हैं कि वे निर्बल हैं; वे इसलिए मांग रही हैं क्योंकि राष्ट्र की नीति-निर्धारण की सर्वोच्च आसंदी पर उनका स्थान रिक्त है। भारत का लोकतंत्र केवल निर्वाचन की व्यवस्था मात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत सामाजिक अनुबंध है, जिसकी पूर्णता महिलाओं की निर्णायक भागीदारी के बिना असंभव है।

आज जब हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाने तत्पर हो रहे हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह अधिनियम दशकों से अधर में लटका हुआ था। पूर्व की सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था, जिसके कारण नारी शक्ति का यह अधिकार फाइलों में दबा रहा। यह अधिनियम केवल और केवल देश के यशस्वी *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी* की अदम्य इच्छाशक्ति और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 'अमृत काल' के इस दौर में यह सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति केवल एक मतदाता समूह नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। मोदी जी ने अपनी माता और बहनों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह अद्वितीय है। चाहे वह रसोई के धुएँ से मुक्ति दिलाने वाली 'उज्ज्वला योजना' हो, घर-घर शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान देने वाला 'स्वच्छ भारत मिशन' हो, या फिर हर घर जल पहुँचाकर माताओं के जीवन को सुगम बनाने का संकल्प—प्रधानमंत्री जी ने सदैव एक 'हितेषी भाई' और 'पुत्र' की भांति देश की महिलाओं की मूलभूत समस्याओं को समझा और उन्हें हल किया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' उनके इसी अटूट समर्पण की अगली कड़ी है, जो महिलाओं को 'लाभार्थी' से उठाकर 'नेतृत्वकर्ता' की श्रेणी में खड़ा करती है।

जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं, तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बेटियों ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी कठिन थी। *रितु करिधाल जी, जिन्हें 'भारत की रॉकेट वुमन' कहा जाता है, उनकी कहानी लखनऊ की तंग गलियों से शुरू होकर मंगल ग्रह की कक्षाओं तक पहुँचती है। मंगलयान मिशन (Mars Orbiter Mission) में 'डिप्टी ऑपरेशन्स डायरेक्टर' के रूप में उन्होंने वह जटिल गणित और गणनाएँ कीं, जिन्होंने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। एक माँ और एक वैज्ञानिक के दायित्वों के बीच संतुलन बिठाते हुए रितु जी ने सिद्ध किया कि महिला का प्रबंधन कौशल ब्रह्माण्ड की जटिलताओं को भी सुलझा सकता है। वहीं, मुथैया वनिता जी का नाम भारत के चंद्रयान-2 मिशन के साथ स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे इसरो (ISRO) के इतिहास में किसी अंतरग्रहीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनीं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियर के रूप में उनका अनुभव और डेटा को समझने की उनकी अद्भुत क्षमता ने भारत के चंद्र अभियान को एक नई ऊँचाई दी। वनिता जी की सफलता यह संदेश देती है कि जब जटिल इंजीनियरिंग और तकनीक की बात आती है, तो भारत की बेटियाँ केवल सहभागी नहीं, बल्कि सर्वोपरि मार्गदर्शक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि अब आसमान भी भारत की बेटियों की सीमा नहीं है।

'परंतु मातृशक्ति की यह उड़ान केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। जब हम वैश्विक क्षितिज पर देखते हैं, तो कल्पना चावला का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने करनाल की मिट्टी से उठकर अंतरिक्ष के तारों तक पहुँचने का साहस दिखाया। वे आज भी हर उस बेटी के लिए प्रेरणा हैं जो अभावों के बीच बड़े सपने देखती हैं।

महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता का एक और प्रकाश स्तंभ सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल रहा। उन्होंने विदेश मंत्रालय को 'रायसीना हिल्स' की फाइलों से निकालकर आम नागरिक के द्वार तक पहुँचा दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि कूटनीति केवल मेज पर होने वाले समझौतों का नाम नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता का नाम है। उनका वह आश्वासन आज भी गूँजता है— ₹यदि आप मंगल ग्रह पर भी फँसे हैं, तो भारतीय दूतावास वहाँ आपकी मदद करेगा।₹ 'ऑपरेशन राहत' के माध्यम से हजारों भारतीयों को सुरक्षित बचाना और वैश्विक मंचों पर हिंदी की गर्जना करना, उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण था।

शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में भी बदलाव की लहर स्पष्ट है। 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण' (AISHE) के अनुसार, उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत कार्यबल महिलाएं हैं। प्रशासनिक जगत में किरण बेदी जैसी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले का चालान काटकर यह संदेश दिया कि विधान की दृष्टि में सत्ता का कोई विशेष मोल नहीं है। यही वह निष्पक्षता और साहस है जिसकी आज हमारी राजनीति को आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब विकास का नेतृत्व महिलाएँ करें। 'मुद्रा योजना' के माध्यम से आज करोड़ों महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन रही हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर सेनाओं में महिलाओं के स्थायी कमीशन तक, मोदी जी ने हर बाधा को दूर किया है। यह अधिनियम उसी श्रृंखला का महा-अनुष्ठान है, जो राजनीति की सर्वोच्च संस्थाओं में महिलाओं की गर्जना सुनिश्चित करेगा। यह प्रधानमंत्री जी का अपनी देश की करोड़ों माताओं-बहनों को दिया गया एक ऐतिहासिक उपहार है।

विश्व भर की संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व आज भी मात्र छब्बीस प्रतिशत है, जबकि भारत तैंतीस प्रतिशत के साथ दुनिया को राह दिखाएगा। यह अधिनियम उस मानसिकता पर प्रहार है जो महिलाओं को केवल 'लाभार्थी' मानती थी; अब वे 'भाग्यविधाता' की भूमिका में होंगी। संसद और विधानसभाओं में यह आरक्षण केवल सीटों का बँटवारा नहीं, बल्कि हमारी राजनीति के चरित्र को बदलने का संकल्प है।

14 लाख महिला जन-प्रतिनिधियों ने पंचायतों में पहले ही अपनी कार्यक्षमता सिद्ध कर दी है। अब समय है कि वे राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करें। यह अधिनियम उन करोड़ों लड़कियों के आत्मविश्वास का विस्तार है, जो अब संसद की दीर्घा को देखकर यह कह सकेंगी- हाँ, मैं भी यहाँ पहुँच सकती हूँ।' जब नारी सशक्त होगी, तभी राष्ट्र वास्तव में समर्थ होगा। प्रधानमंत्री जी के इस महान संकल्प के साथ, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि की पहचान हमारी मातृशक्ति हो।

# लेकिन शहरी माओवाद पर कैसे लगे लगाम

बीते तीस मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहे माओवादी और नक्सली आतंकवाद के खात्मे का औपचारिक अंत की घोषणा कर दी है। चाहे माओवाद हो या नक्सलवाद, दोनों ही धाराएं उग्रपंथी वामपंथ से प्रभावित रही हैं। इनका मानना रहा है कि सत्ता बंदूक की नली या बारूद से निकलती है। इसी विचारधारा के तहत इस वैचारिकी ने भारत के तकरीबन एक तिहाई जिलों पर अरसे तक कब्जा जमाए रखा। इस विचारधारा से प्रभावित लाल आतंक एक दौर में पशुपति से लेकर तिरूपति तक फैला हुआ था। लेकिन अब यह निस्तेज हो चुका है। ज्यादातर नक्सली या माओवादी लड़ाके या तो हथियार डाल कर मुख्यधारा की जिंदगी में वापस लौट गए हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन अब भी इस विचारधारा से प्रभावित एक वर्ग बचा हुआ है। जिसका सत्ता के प्रतिष्ठानों पर भले ही प्रभाव ना हो, लेकिन तंत्र पर उसका प्रभाव अब भी है। मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी। 'द कश्मीर फाइल्स' नामक इस फिल्म में एक संवाद है, सत्ता भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम अपना है। इस संवाद में जिस सिस्टम की ओर इशारा है, दरअसल तंत्र पर उसका ही प्रभाव है। कहना न होगा कि यह प्रभावी तबका वैसी ही उग्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके बारूदी रूख के अंत का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं ने इसे 'अर्बन नक्सल' कहा था। अर्बन यानी शहरी नक्सल। याद कीजिए, छह अप्रैल 2010 की घटना, जब बस्तर में सीआरपीएफ के 74 जवानों को घेरकर नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों के जरिए उड़ाकर मार डाला था। इस लोमहर्षक कार्रवाई भारतीय राष्ट्र राज्य पर अर्बन नक्सल समुदाय ने बड़ी जीत के रूप में देखा था। राजधानी दिल्ली में लाल गढ़ के रूप में विख्यात जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने इस कार्रवाई पर खुलेआम खुशियां जताई थीं। तमाम विश्वविद्यालयों के वामपंथी प्रोफेसरों और छात्रों के एक समूह ने इस लोमहर्षक हत्या कांड को भारतीय राज व्यवस्था पर नक्सली जीत के रूप में लिया था। बस्तर की इस घटना के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार सकते में थी। उसने समानांतर सत्ता चला रहे नक्सली और माओवादी आतंकियों पर हवाई कार्रवाई करने का विचार शुरू कर दिया था। लेकिन शहरी इलाकों के वामपंथी बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध शुरू किया। तंत्र में इनकी उपस्थिति कितनी प्रभावी है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनमोहन सरकार ने नक्सली हिंसा का प्रभावी जवाब देने का विचार त्याग दिया था। नक्सलवाद कहें या माओवाद या फिर वामपंथ की कोई अन्य धारा, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, पत्रकारिता, स्वयंसेवी संगठनों, वकालत, अस्पतालों, प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारीतंत्र में भी इनके प्रभावी लोग अब भी मिल जाएंगे। अरूंधती रॉय, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी तो खुद ही मानते हैं कि वे इस विचारधारा से हैं। तंत्र में इस विचारधारा के प्रभावी होने की शुरूआत 1969 में कांग्रेस के विभाजन से होती है। तब अपनी केंद्रीय सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को वामपंथी दलों के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने सहयोग किया भी, बदले में शैक्षिक संस्थानों पर उनका प्रभाव बढ़ा। इसकी वजह यह रही कि इंदिरा सरकार ने शोध और शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को इन्हीं के हवाले कर दिया। इस विचारधारा ने अपने ही लोगों को इन संस्थानों में खूब भरा। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो यह वैचारिकी पहले सकते में रही। बाद में इसने रणनीति और पैंतरा बदला। शुरू में तो इस विचारधारा ने कभी पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में वैचारिकी आधारित आंदोलन छेड़ा तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों से छेड़खानी के बहाने राष्ट्रवादी विचाराधारा को निशाने पर लेकर आंदोलन चलाया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित बेमुला के बहाने राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था के दौरान कथित तौर पर दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर वैचारिक आंदोलन खड़ा किया। दो कृषि कानूनों के बदलाव के विरोध में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को भी इस वैचारिकी का खुला समर्थन रहा। टूल किट गिरोह इसी दौरान बेपर्दा हुए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर के अल्पसंख्यकों को भड़काने और उन्हें आंदोलन में लाने के पीछे भी यही विचारधारा रही। इन आंदोलनों के लंबे समय तक चलने, इनके लिए लोगों के एकत्रित होने की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी नक्सलियों का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितनी गहराई तक उनकी पहुंच है।

# भारत की जनगणना 2027: बदलते भारत की नई कहानी

## हमारी जनगणना-हमारा विकास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ तैयार

**रमेश जायभाये**

**भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और 1881 से इसे पूरे देश में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित हुई**

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छोटी-सी जानकारी—जैसे पानी, बिजली या परिवार के सदस्यों का विवरण—देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकती है? दरअसल, हर नागरिक की दी गई जानकारी मिलकर ही भारत के भविष्य की दिशा तय करती है। इसी कड़ी में वर्ष 2027 की जनगणना एक खास पड़ाव बनने जा रही है। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक नई कहानी है—एक ऐसी कहानी जिसमें हर नागरिक की भागीदारी है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल अंदाज़ में होगी, जो इसे पहले की सभी जनगणनाओं से अलग और अधिक आधुनिक बनाती है। छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान को लेकर तैयारियाँ तेज़ी से पूरी की जा रही हैं। वातावरण ऐसा है मानो कोई बड़ा जनउत्सव आने वाला हो—और वास्तव में, यह एक ऐसा अभियान है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और 1881 से इसे पूरे देश में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित हुई, जिसने देश के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई।

अब वर्ष 2027 की जनगणना इस ऐतिहासिक यात्रा का आधुनिक रूप है। यह न केवल देश की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी, बल्कि भविष्य की योजनाओं की नींव भी तैयार करेगी।

छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी—पहला चरण अप्रैल-मई 2026 में और दूसरा फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा। राज्य के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (रात 12 बजे) निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी।

इस बार जनगणना की सबसे रोचक और उपयोगी सुविधा है—स्व-गणना। अब आप स्वयं अपने घर और परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आपसे परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा, व्यवसाय और घर की सुविधाओं से जुड़े कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी भरने के बाद आपको एक एसई आईडी प्राप्त होगी। जब प्रगणक आपके घर आएंगे, तो केवल यह पहचान दिखानी होगी और आपकी जानकारी सत्यापित कर ली जाएगी—यानी बार-बार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आप जो जानकारी देंगे, वही दर्ज की जाएगी। स्व-गणना के प्रति लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है—देशभर में लाखों परिवार इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं, जो इस डिजिटल पहल की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इस बार जनगणना पूरी तरह तकनीक के सहारे संचालित होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे, जिससे काम तेज़ और अधिक सटीक होगा। साथ ही, आधुनिक जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर हर क्षेत्र और गणना ब्लॉक को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है, ताकि कोई भी घर या व्यक्ति छूट न जाए। डेटा के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए उन्नत डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, इस बार जाति संबंधी आंकड़ों का भी समावेश किया जाएगा, जो दशकों बाद समाज की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा।

जनगणना में समाज के हर वर्ग को शामिल करने का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी के तहत बेघर व्यक्तियों की गणना भी अलग से, विशेष अभियान के माध्यम से की जाती है, ताकि कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। और जहाँ तक आपकी जानकारी की सुरक्षा का सवाल है—यह पूरी तरह गोपनीय रहती है। इसे किसी अन्य विभाग या एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं। शहरों से लेकर गाँवों तक, हर क्षेत्र में जनगणना टीम सक्रिय रहेगी, ताकि कोई भी परिवार छूट न जाए।

नागरिकों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है, जहाँ किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस पूरे अभियान की असली ताकत है—आपकी भागीदारी। जब आप सही जानकारी देते हैं, तो आप केवल एक फॉर्म नहीं भरते, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं। आपकी दी गई जानकारी से ही तय होता है कि कहाँ नई सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल खुलेगा और कहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है।

जनगणना एक आईना है, जिसमें देश खुद को देखता है। इस बार यह आईना डिजिटल है—तेज़, सटीक और आधुनिक। और इसमें जो तस्वीर दिखेगी, उसे बनाने में आपका भी योगदान होगा। तो आइए, इस जनगणना अभियान का हिस्सा बनें—स्व-गणना करें, सही जानकारी दें और देश के विकास की कहानी में अपनी भूमिका निभाएं।

**लेखक उपनिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय हैं**

## टिप्पणी

# बच्चों को गहरा नुकसान

कोर्ट ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स बनाए। बच्चों पर उनके संभावित दुष्प्रभाव के बारे में उन्होंने पूर्व चेतावनी नहीं दी। इस कारण कोर्ट ने उन पर लगभग 60 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर जानबूझ कर ऐसी तकनीकी व्यवस्था की है, जिससे यूजर्स को उन पर बने रहने की लत लग जाती है। खासकर बच्चों को इससे गहरा नुकसान हो रहा है। अमेरिका में कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक दूरगामी महत्त्व का फैसला दिया। उसमें सोशल मीडिया कंपनियों मेटा (इंस्टाग्राम) और गूगल (यूट्यूब) को बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य हानि पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने पाया कि इन प्लेटफॉर्म्स ने एडिक्टिव डिजाइन (लत डालने वाले) फीचर्स बनाए। बच्चों पर उनके हो सकने वाले दुष्प्रभाव के बारे में उन्होंने कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी। इस कारण कोर्ट ने उन कंपनियों पर लगभग 60 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

यह फैसला एक 20 वर्षीय महिला की याचिका पर आया, जिसने बताया कि बचपन से ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के उपयोग ने उसके जीवन पर खराब असर डाला और उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाईं। इस फैसले को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पहला बड़ा कानूनी झटका माना गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब मेटा और गूगल जैसी कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन बदलने और उन्हें बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए दबाव बढ़ेगा। मगर ये बात अमेरिका के अंदर की है। बाहर में जब कभी किसी देश ने इन कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है, अमेरिका सरकार अपनी कंपनियों के बचाव में आ खड़ी हुई है।

डॉनल्ड ट्रंप के शासनकाल में यह प्रवृत्ति अधिक आक्रामक नजर आई है। विनियमन की यूरोपियन यूनियन की कोशिश के खिलाफ ट्रंप खुद मोर्चा संभाले रहे हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच रोकने के ठोस कदम उठाए हैं। भारत में भी ऐसी चर्चा हाल में तेज हुई है। कर्नाटक सरकार ने इस दिशा में पहल की है। मगर जब ऐसा कदम केंद्र के स्तर पर नहीं उठाया जाता, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है। अतः नरेंद्र मोदी सरकार को कम-से-कम इस मामले में अमेरिकी दबाव की परवाह ना करते हुए ठोस वैधानिक पहल करनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ कंज्यूमर समझने वाली कंपनियों को विनियमित करने की अति-आवश्यकता है।

## ब्लॉग

# क्या नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक, प्रशासनिक व राजनीतिक साठगांठ जिम्मेदार है?

**कमलेश पांडे**

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है।

हमारे देश के राजनेता भले ही चुनावों के दौरान दलित-महादलित-आदिवासी, ओबीसी-ईबीसी, अल्पसंख्यक-पसमांदा और गरीब सवर्ण आदि से जुड़े सामाजिक न्याय सम्बन्धी तरह-तरह की बातें करते हैं, ममनगढ़ंत आंकड़े गिनाते/बताते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे श्रमजीवियों का अंतहीन शोषण होता रहता है, जिससे उनका मुंह फेरे रहना या फिर किसी बड़े आंदोलन के बाद सक्रिय होना उनके नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाता है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है।

यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं। विपक्ष का काम संसद में, विधान मंडल में इन्हीं पहलुओं पर तर्कसंगत बहस करना है, लेकिन वह भी नीतिगत नकारापन का शानदार नमूना बन चुका है। दिलचस्प तो यह कि पहले सत्ताधारी यूपीए के वक्त एनडीए विपक्ष में था और अब सत्ताधारी एनडीए के वक्त यूपीए/इंडिया गठबंधन विपक्ष में है। चूंकि दोनों पूंजीवादी गठबंधन हैं और अपने आर्थिक मोहपाश में जनोन्मुखी समाजवादी व वामपंथी सियासत को बांध चुके हैं, जिससे सबकुछ गड्डमड्ड हो चुका है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद और कहीं सम्प्रदायवाद के नाम पर परस्पर बंटी हुई जनता को अपनी मौलिक जरूरतों का एहसास ही नहीं है।

काबिलेगौर है कि शहरों/महानगरों या गांवों में जो आमतौर पर वेतन स्ट्रक्चर होता है, उससे कोई युवा या वयस्क अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सकता है क्या? जवाब होगा- संभव नहीं! कोढ़ में खाज यह कि तरह तरह के मित्रों- शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र आदि के मार्फ़त सरकारी क्षेत्र भी इन्हीं पूंजीवादी मानसिकता को तरजीह देता आया है, जिस पर उदार हृदय से बहस करने और भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है। सवाल है कि जिन शहरों में फ्लैट्स या जमीन की कृत्रिम कीमतें आसमान छूती हों, वहां के दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी, अंशकालिक/पूर्णकालिक श्रमिकों के वेतनमान, और भारतीय कानूनों से अधिकारियों/उद्योगपतियों के खिलवाड़ से पूरी श्रम व्यवस्था विस्फोटक कगार पर खड़ी है। शहरों में बढ़ता झुग्गी-झोपड़ी कल्चर किसी नैतिक महामारी जैसा प्रतीत होता है।

सुलगता सवाल है कि निजी क्षेत्र में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं निजी कम्पनियों में मिलती है। प्रोपर्टी इंडस्ट्री की तरह आधा ब्लैक सैलरी और आधा व्हाइट सैलरी वाली आंखों में धूल झोंकने वाली व्यवस्था से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सरकारी क्षेत्रों की तरह आवासीय सुविधाओं से निजी क्षेत्र के श्रमिकों को वंचित क्यों रखा जाता है? नौकरी बाजार में श्रम ठेकेदार पैदा करने से किसके हित सधते हैं? सवाल अनेक हैं, लेकिन उत्तर एक- राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक सांठगांठ से जारी नीतिगत भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है, जो किसी बड़ी जनक्रांति के बाद ही करवट लेगी।

जरा कल्पना कीजिए कि जब नरेंद्रमोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी मजदूर विरोधी परिस्थिति है तो पूर्व की सरकारों में कैसा जंगलराज रहा होगा, विचारणीय पहलू है। मजदूर शोषण कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम भारतीयों के भविष्य के साथ एफडीआई आकर्षित करने के चक्कर में घोर अन्याय हो रहा है, जिससे बचे जाने की जरूरत है। अब नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं। चूंकि नोएडा में मजदूरों का हिंसक आंदोलन वेतन वृद्धि की मांग पर केंद्रित है, जो हरियाणा की 35% न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी से प्रेरित है। लिहाजा, योगी सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए। बताया गया कि यह प्रदर्शन फेज-2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूरे नोएडा में फैल गया, जहां पेशेवर विपक्षी आंदोलनों के तर्ज ओर तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने संवाद के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है और अविलंब इसके निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की बात है तो योगी सरकार ने आंदोलन को साजिश, नक्सलवाद या राजनीतिक हाथ बताया, जिससे सहमत होना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के हिंसक होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत भी नहीं हैं। वहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की 'पूंजीपति पक्षधर' नीति को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर शोषण का आरोप लगाया, जो अतिरेक है। चूंकि कांग्रेस और सपा ने सरकार की आलोचना की, इसलिए केंद्र भी सतर्क है। इस अप्रत्याशित आंदोलन का प्रमुख निहितार्थ यह है कि यह आंदोलन श्रम नीतियों पर बहस तेज कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों से अंतरराज्यीय दबाव बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को मजदूर वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को कानून-व्यवस्था पर खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ी।दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी।

यह कोरा सच है कि नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक-प्रशासनिक-राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है। नोएडा मजदूर आंदोलन 2027 यूपी विधानसभा चुनावों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह श्रमिक असंतोष को विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी ताजा घटना होने से विश्लेषण अनुमानित हैं, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इससे विपक्ष को लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की 'पूंजीपति नीति' बताकर मजदूरों का समर्थन किया, जो पीडीए (PDA) यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और विपक्षी एकता का संकेत दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक वोट (गौतमबुद्धनगर सीटें) प्रभावित हो सकते हैं। इससे भाजपा की जमीनी चुनौती बढ़ेगी और हिंदुत्व दम तोड़ देगा, इसलिए योगी सरकार ने वेतन, ओवरटाइम सम्बन्धी निर्देश देकर क्षतिपूर्ति की कोशिश की, लेकिन इसे 'साजिश' बताकर विपक्ष को और हवा मिली। कानून-व्यवस्था का सवाल उठा, जो भाजपा के 'मजबूत सरकार' वाले नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे दिल्ली-एनसीआर में आंदोलन के फैलाव से पश्चिम यूपी की सीटें जोखिम में पड़ सकती हैं। वहीं, श्रम मुद्दा, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी से जुड़कर 2027 में प्रमुख हो सकता है, खासकर ग्रेटर नोएडा-जेवर जैसे क्षेत्रों में। इसलिए यदि समाधान न हुआ तो विपक्ष मजबूत, वरना भाजपा इसे 'विकास' के पक्ष में पलट सकती है। कुल मिलाकर, नोएडा रणभूमि बन चुका है।

# मणिपुर की लड़की की झांसी में संदिग्ध मौत, कब्रिस्तान में शव दफनाने पहुंचा बॉयफ्रेंड, पति ने पहुंचकर जमकर काटा बवाल

**आर्यावर्त संवाददाता**

**झांसी।** उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कब्रिस्तान में जमकर हंगामा हो गया। मृतका का बॉयफ्रेंड शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था, लेकिन वहां पहचान पत्र न होने के कारण कर्मचारियों ने दफनाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान युवती का पति मौके पर पहुंच गया और हत्या का आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा हो गया।

मृतका की पहचान सिम्मी उर्फ टेरेसा (30) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मणिपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी करीब 10 साल पहले जॉन नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहते थे, लेकिन नवंबर 2025 में टेरेसा झांसी आ गई थी। यहां वह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा इलाके में स्थित एक मसाज पार्लर में काम करने लगी थी।

### 10 दिनों से बीमार थी सिम्मी

बताया जा रहा है कि पार्लर में काम के दौरान सिम्मी की दोस्ती एक महिला सहकर्मी से हुई और वह उसी के घर रहने लगी। इसी दौरान सहकर्मी के भाई से उसकी नजदीकियां बढ़ीं और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सहकर्मी के मुताबिक, सिम्मी पिछले करीब 10 दिनों से बीमार थी और उसका इलाज कराया जा रहा था। बुधवार शाम उसकी अचानक मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। मौत के बाद उसका कथित प्रेमी शव को लेकर जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान पहुंचा, जहां बिना

पहचान पत्र के शव लाने पर कर्मचारियों ने दफनाने से मना कर दिया। इसके बाद शव को कानपुर चुंगी क्षेत्र के एक अन्य कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन वहां भी अनुमति नहीं मिली। इसी बीच मृतका का पति जॉन अपने परिचितों के साथ मौके पर पहुंच गया और मौत पर संदेह जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

### पति ने लगाए गंभीर आरोप

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी की हत्या की गई है और बिना उचित प्रक्रिया के शव को दफनाने की कोशिश की जा रही थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नवाबाद थाना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जॉन के दोस्त अमन सिंह के अनुसार, उन्हें रास्ते में कई बार फोन कर शव को जल्दी दफनाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि जॉन ईसाई धर्म से हैं, इसलिए अंतिम संस्कार चर्च की परंपराओं के अनुसार होना चाहिए था। वहीं कब्रिस्तान समिति के सदस्य मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि बिना पहचान पत्र शव लाए जाने की सूचना मिलने पर दफनाने से इनकार किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

# महिला शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी को लेकर उठाई आवाज, बीएसए को सौंपा ज्ञापन

**आर्यावर्त संवाददाता**

**सुलतानपुर।** उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष डॉ. गायत्री सिंह के नेतृत्व में महिला शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता से मिला और जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में एक मांग पत्र सौंपा महिला शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण बच्चों के विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए गंभीर रूप से बीमार शिक्षिकाओं को जनगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही गर्भवती शिक्षिकाओं को भी इस कार्य से दूर रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षकों के लिए आवागमन हेतु उचित साधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उचित मानदेय दिया जाए और ड्यूटी पूर्ण होने के बाद नियमानुसार अवकाश भी प्रदान किया जाए।

# अधिवक्ता परिषद अवध इकाई ने समरसता दिवस के रूप मे मनाया डा. अम्बेडकर जयंती

**आर्यावर्त संवाददाता**

**सुलतानपुर।** अधिवक्ता परिषद अवध इकाई सुल्तानपुर द्वारा दीवानी न्यायालय मे स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद हाल मे डॉ भीम राव रामजी अम्बेडकर के 135वें जन्मदिन को समरसता दिवस के रूप मे मनाया गया। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप में मुक्ता त्यागी जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुल्तानपुर उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुवात भारत माता एवं डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिश्चन्द्र दुबे एडवोकेट अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद अवध इकाई सुल्तानपुर तथा संचालन महामंत्री सर्वेश कुमार मिश्रा ने की. कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्दर शर्मा एडवोकेट, अनिल शुक्ला एडवोकेट, नागेंदर सिंह एडवोकेट, आदि ने सम्बोधित किया. जिसमे डॉ अम्बेडकर के द्वारा बताए गए सिद्धांतो एवं संविधान में प्रदत्त कानूनो पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुवे मुख्य वक्ता अतिथि द्वारा कहा गया कि हम सब को संविधान में दिये कानूनो का पालन करते हुवे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए. अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा आये हुये अतिथि एवं अधिवक्ता बन्धुओं का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

## प्रधान मंत्री किसान निधि योजना से 62,638 अपात्र हटाये

**जौनपुर।** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 62,638 अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि पति-पत्नी, नाबालिग और मृतक भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। इस कार्रवाई के बाद जिले में लाभार्थियों की कुल संख्या 8 लाख 79 हजार 300 से घटकर 8 लाख 16 हजार 662 हो गई है।योजना के शुरुआती चरण में बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों ने पंजीकरण करा लिया था। अब जांच के बाद ऐसे अपात्रों की पहचान कर उनके नाम पोर्टल से हटाए जा रहे हैं। पात्रता की जांच के लिए गांवों में शिविर लगाए गए और सूची का मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में 29 हजार मृतकों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं, जिनके परिवारों ने मृत्यु की सूचना विभाग को नहीं दी थी। इसके अलावा, लगभग 22 हजार ऐसे लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है, जिस कारण उनकी धनराशि रोक दी गई है।उप परियोजना निदेशक आत्मा, डॉ. रमेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अपात्रों के नाम हटाए गए हैं।

# 'देखने लायक हो तो देखेंगे'... बीएचयू गेट पर युवती से बदतमीजी, स्कॉर्पियो सवार मनचलों की हरकत

**आर्यावर्त संवाददाता**

**वाराणसी।** उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के हैदराबाद गेट के पास एक युवती के साथ बदतमीजी और अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार युवकों की इस हरकत का युवती ने न केवल कड़ा विरोध किया, बल्कि अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए उनका वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाराणसी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को बीएचयू कैंपस से सटे हैदराबाद गेट के पास स्कॉर्पियो सवार कुछ युवकों ने वहां से गुजर रही युवती पर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां कीं। जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी और ज्यादा बदतमीजी करने लगे। स्थिति को देखते हुए युवती ने तुरंत शोर मचाया और अपने मोबाइल

फोन से युवकों तथा उनकी गाड़ी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर बढ़े, लेकिन तब तक आरोपी तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो लेकर फरार हो चुके थे।

### वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

घटना के बाद युवती द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन की पहचान की और घेराबंदी कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

### मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीप नारायण सिंह (29 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज (न्यू कॉलोनी) का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय स्कॉर्पियो में दीप नारायण सिंह के साथ एक और युवक भी मौजूद था। उसकी पहचान की जा रही है और पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

### आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

## नारी शक्ति वंदन के समर्थन में छात्राओं ने बनाई रंगोली

**जौनपुर।** पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के आर्यभट्ट सभागार में शुक्रवार को एक संसदीय सत्र का आयोजित किया गया। कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से आयोजित किया गया, जहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए महिलाओं के सशक्त नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के संकल्प को दोहराया। पूरे आयोजन के दौरान सभागार में गंभीरता, जागरूकता और उत्साह का वातावरण बना रहा।सभी प्रतिभागियों ने सजीव प्रसारण को ध्यानपूर्वक देखा और इसे भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने तथा समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का सामूहिक संकल्प लिया। पर कुलसचिव केशलाल, परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, कार्यक्रम संयोजक डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव एवं अन्य शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

# महिला सशक्तिकरण को लेकर पुलिस विभाग ने किया भव्य सम्मेलन का आयोजन

**आर्यावर्त संवाददाता**

**सुलतानपुर।** उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम (फेज-5) के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस विभाग की ओर से पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने की, जबकि आयोजन का संयोजन अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह द्वारा किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता कर महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी

भूमिका को सशक्त बनाने पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा सभी वक्ताओं को पौध भेंट कर सम्मानित किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सम्मान की एक सकारात्मक पहल भी रही। कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इनमें प्रदेश संगठन मंत्री अनूप श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष रमेश अग्रहरि (लंभुआ), महामंत्री नियाज राइन (धनपतगंज), अध्यक्ष मनोरमा जायसवाल (अहिमाने), महामंत्री दिनेश अग्रहरि (जयसिंहपुर) एवं वरिष्ठ व्यापारी रवीन्द्र मोदनवाल सहित अन्य पदाधिकारी व उद्यमी शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन नारी शक्ति वंदन, अभिनंदन के संदेश के साथ हुआ, जिसमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई।

## अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर छापा

**जौनपुर।** मुंगराबादशाहपुर में स्थित शक्ति स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में संचालित एक अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। इस दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत चार संदिग्ध दवाओं के नमूने जब्त किए गए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। जिला औषधि निरीक्षक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में अस्पताल के भीतर बिना वैध लाइसेंस के दवाओं के अवैध कारोबार का आरोप लगाया गया था। सहायक आयुक्त औषधि, वाराणसी मंडल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिले में अवैध रूप से संचालित दवा दुकानों और प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की थी। जिला औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक वाराणसी चंद्रेश द्विवेदी और औषधि निरीक्षक गाजीपुर बृजेश कुमार मौर्य की संयुक्त टीम ने अस्पताल में छापेमारी की।

# एक रसगुल्ला मांगने की ऐसी सजा... शादी में आए मासूम को कारीगर ने जलते तंदूर में फेंका, हालत नाजुक

**आर्यावर्त संवाददाता**

**बस्ती।** उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव में एक विवाह समारोह के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महज एक रसगुल्ले के विवाद में कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक 11 वर्षीय बच्चे को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। आग की लपटों से बच्चा चेहरे से लेकर कमर तक बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर अवस्था में लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, गोंडा जिले के नवाबगंज थानांतर्गत दुर्जनपुर निवासी चमन (11) पुत्र संतोष, अपनी मां के निधन के बाद से ही बस्ती के बाघानाला स्थित अपने ननिहाल में रह रहा था। बुधवार को वह अपनी नानी के साथ मलौली

गोसाई गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शादी में खुशी का माहौल था और चमन खेल-कूद रहा था। इसी दौरान वह भोजन स्थल पर गया और वहां रखे रसगुल्ले निकाल कर खाने लगा। आरोप है कि बार-बार रसगुल्ला निकालने पर वहां मौजूद कैटरिंग ठेकेदार अपना आपा खो बैठा। उसने पहले बच्चे को पकड़कर डराया और फिर उसे उठाकर जलते हुए तंदूर के ऊपर कर दिया। इसी बीच अनियंत्रित होकर बच्चा सीधे तंदूर के भीतर जा गिरा।

तंदूर से बच्चे की चीखें सुनकर शादी समारोह में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में परिजनों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। उसे तत्काल अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी ठेकेदार मौके से फरार हो गया।

### तंदूर कारीगर के खिलाफ केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पीड़ित के मामा देवीदीन निषाद ने आरोपी तंदूर कारीगर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि दुर्घटना में एक बच्चा आग में जल गया है, जिस मामले में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

### परिजनों में भारी गुस्सा

गौरतलब है कि पीड़ित बच्चे चमन के सिर से मां का साया पहले ही उठ चुका था। वह अपने ननिहाल बाघानाला में रहकर कक्षा दो में पढ़ाई कर रहा था। नानी के साथ वह खुशी-खुशी शादी में शामिल होने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी मासूमियत पर कोई इतना भारी पड़ेगा। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी करने वाले अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

# नोएडा में बनेंगी मेट्रो की तीन और लाइनें, किन इलाकों को होगा फायदा, कब होगी शुरुआत?

**आर्यावर्त संवाददाता**

**नोएडा।** दिल्ली-NCR में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाले तीन नए मेट्रो रूट प्रस्तावित हैं। इसमें बॉटनिकल गार्डन लिंक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट कनेक्टिविटी और बोडाकी ट्रांसपोर्ट हब शामिल है।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार अगले 5 साल में ये तीन नए मेट्रो रूट संचालित हो जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंबे समय से मेट्रो की मांग भी हो रही है। मेट्रो के विस्तार का सबसे बड़ा असर यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी के अवसर और कारोबार भी पड़ेगा।

### सबसे अहम है ये प्रोजेक्ट

सबसे अहम प्रोजेक्ट है एक्वा लाइन का विस्तार, जो सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक करीब 11।5 किमी लंबा होगा और इसमें 8 नए स्टेशन बनाए जाने की योजना है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए डिटेल सर्वे का काम चल रहा है, जो करीब तीन महीने में पूरा होने की संभावना है। उसके बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।

### सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट

दूसरी तरफ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए भी मेट्रो कनेक्टिविटी पर काम जारी है, हालांकि इसमें चरणबद्ध तरीके से स्टेशन बनाए जाएंगे। यह इलाका तेजी से बढ़ती आबादी का केंद्र बन चुका है, जहां लाखों लोग रहते हैं और लंबे समय से बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग कर रहे हैं।नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट से लिए संशोधित डीपीआर तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इसे केंद्र सरकार के पास भेजा।

तीसरा अहम प्रोजेक्ट बोडाकी मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से जुड़ा है, जहां मेट्रो, रेलवे और बस सेवाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इस रूट पर मेट्रों निर्माण का काम अगले करीब 7 महीने में शुरू हो सकता है।

## अध्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयाय करें

**जौनपुर।** प्राथमिक विद्यालय रामपुर गजाधर, मुंगराबादशाहपुर के परिसर में वार्षिकोत्सव, प्रवेशोत्सव, सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन एवं सेवानिवृत शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल द्वारा मॉ सरस्वती जी एवं डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम देकर स्वागत किया गया। प्रवक्ता गिरिजा शंकर इंटर कॉलेज नीभापुर जयकिशन यादव एवं अनुचर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव राम सिंह को अंगवस्त्र एवं बुके देकर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।बीएसए ने कहा कि विकासखंड मुंगराबादशाहपुर के किसी भी बस्ती मजरे का 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा नामांकन से छूटने न पाए तथा नामांकित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अध्यापकों का उत्साह वर्धन किया गया।

# जमीन विवाद में थानाध्यक्ष हलियापुर पर महिला की पिटाई करने का आरोप

**आर्यावर्त संवाददाता**

**सुलतानपुर।** जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक चारू निगम से शिकायत कर न्याय की मांग की है।

मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम डेहरियावा का है, जहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गांव निवासी पूजा पत्नी बदलू के अनुसार, बीते 12 अप्रैल को उसके पट्टीदार रोघई अपने पुत्र राहुल के साथ उसके ससुर राम निहोर पर हमला करने के इरादे से दौड़े। बीच-बचाव करने पहुंची पूजा के साथ भी राहुल द्वारा मारपीट की गई।

आरोप है कि घटना के बाद विपक्षी पक्ष ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे

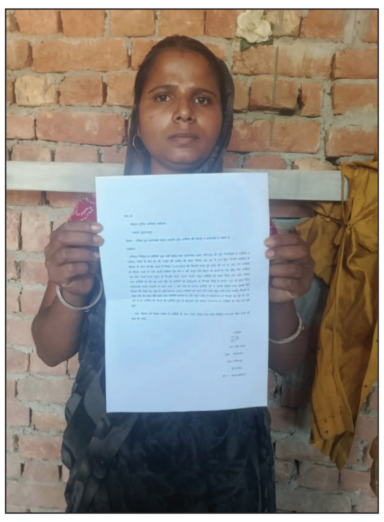

हलियापुर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस पूजा और विपक्षी पक्ष की एक लड़की को थाने ले गई, जबकि मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि थाने ले जाकर महिला थानाध्यक्ष ने उसके साथ डंडे और पट्टे से मारपीट की तथा जातिसूचक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़िता दर्द से कराहती रही बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि थानाध्यक्ष विपक्षी को एक भी गाली तक नही दिया। पीड़िता का कहना है कि न्याय दिलाने के बजाय पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने आशंका जताई है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है और भविष्य में दोबारा प्रताड़ति किया जा सकता है। इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराकर विधिक कार्रवाई करने व न्याय दिलाने की मांग की है।

# खाना बनाना सीखना चाहते हैं? इन 5 तरीकों से बढ़ाएं अपनी रसोई की काबिलियत

खाना बनाना एक कला है, जिसे सीखना और सुधारना कभी भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप रसोई में नई-नई चीजें बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीकों से आप अपनी रसोई की काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप न केवल खाना बनाना सीखेंगे, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी खुश कर सकेंगे। इन तरीकों से आप रसोई में अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे।

### रसोई की सफाई और व्यवस्था बनाए रखें

रसोई की सफाई और व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। इससे न केवल काम करने में आसानी होती है, बल्कि आपको हर चीज आसानी से मिल भी जाती है। रोजाना अपने किचन के काउंटर को साफ करें, बर्तन तुरंत धो लें और सामग्री को सही जगह पर रखें। इसके अलावा हर हफ्ते अपने मसाले और खाने की चीजों को व्यवस्थित करें ताकि आपको पता रहे कि कौन-सी सामग्री कहां रखी हुई है।

### सरल रेसिपी से शुरुआत करें

अगर आप नए हैं तो सरल रेसिपी से शुरुआत करें। जैसे कि सूप, सलाद या आम पकोड़ी आदि। इनसे आपको बुनियादी तकनीकें सीखने को मिलेंगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धीरे-धीरे आप अधिक जटिल व्यंजन भी बना सकेंगे। इसके अलावा इन सरल रेसिपीज से आप अलग-अलग मसालों और सामग्रियों का उपयोग भी सीखेंगे, जिससे आपके खाने का स्वाद और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर होंगे। इस तरह आप खाना बनाने में माहिर हो जाएंगे।

### ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का करें उपयोग

आजकल इंटरनेट पर कई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो चैनल्स, ब्लॉग्स और ऐप्स की मदद से आप नई-नई रेसिपी सीख सकते हैं और उन्हें घर पर आजमा सकते हैं। इन ट्यूटोरियल्स से आपको अलग-अलग तकनीकों और टिप्स मिलेंगे, जो आपके खाना बनाने के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन समुदाय का हिस्सा बनकर अन्य लोगों से भी सीख सकते हैं।

### सही उपकरणों का करें चयन

खाना बनाने के लिए सही उपकरणों का होना बहुत जरूरी है। अच्छे चाकू, कटिंग बोर्ड, पैन और बर्तन रखें ताकि काम आसानी से हो सके। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर जैसी चीजें भी आपकी रसोई को सुविधाजनक बनाएंगी। सही उपकरणों से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपका काम भी आसान होगा। इनसे आप अधिक कुशलता से खाना बना सकेंगे और आपके व्यंजनों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

### धैर्य रखें और प्रयोग करते रहें

खाना बनाना एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आप बेहतर होंगे। लगातार प्रयोग करते रहने से आपकी तकनीक सुधरेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई की काबिलियत बढ़ा सकते हैं और खाना बनाना सीख सकते हैं। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।

# गर्मियों के दौरान ड्रैगन फ्रूट से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, देंगे ठंडक और ताजगी

ड्रैगन फ्रूट एक खास और पौष्टिक फल है। यह न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। गर्मियों में इसकी ताजगी और मिठास का आनंद लेना खासतौर पर सुखद लगता है। आइए आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

### ड्रैगन फ्रूट शेक

ड्रैगन फ्रूट शेक एक बेहतरीन पेय है, जो आपको गर्मियों में तरोताजा रख सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें, फिर उसमें दूध, चीनी (स्वादानुसार) और थोड़ी-सी बर्फ डालकर अच्छे से मिला लें। जब यह मिश्रण एकसार हो जाए तो उसे गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी बर्फ डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपको ऊर्जा देंगे।

### ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम

गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का मजा ही कुछ अलग होता है। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मिक्सर में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें और अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को एक बर्तन में डालकर उसमें मीठा गाढ़ा दूध, मलाई और थोड़ा-सा दूध मिलाएं। इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह जम जाए तो इसे निकालकर परोसें।

### ड्रैगन फ्रूट सलाद

ड्रैगन फ्रूट सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े, सेब, केला और अंगूर डालें। अब ऊपर से थोड़ी-सी दही, शहद और नींबू का रस डालकर सबको अच्छे से मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

### ड्रैगन फ्रूट पैनकेक

सुबह के नाश्ते में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट पैनकेक बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और दूध मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें कटे हुए ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े डालें। तवे पर थोड़ा-सा तेल गर्म करके इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। आप ऊपर से अन्य फल भी डाल सकते हैं।

### ड्रैगन फ्रूट मूस

अगर आप कोई हल्की-फुलकी मिठाई खाना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट मूस चखकर देखें। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में मलाई फेंट लें, फिर इसमें मीसा हुआ ड्रैगन फ्रूट का पेस्ट मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा मीठा गाढ़ा दूध डालें और सबको अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण को कप या गिलास में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह पूरी तरह सेट हो जाए तो इसे निकालकर परोसें।

# हीटवेव का खतरा! भरी गर्मी से बचाने में कारगर हैं ये आयुर्वेदिक तरीके

**उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में कभी बारिश तो कभी गर्मी का मौसम बना हुआ है  लेकिन आने वाले दिनों भीषक गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में आप खुद को पहले से तैयार कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं...**

अप्रैल का महीना चल रहा है और फिलहाल बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है।  लेकिन आने वाले समय में भीषण गर्मी पड़ेगी और इसमें हीटवेव या हीटस्ट्रोक का खतरा बना रहता है।  गर्मी इस कदर पड़ती है कि बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है।  आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को गर्मी बर्दाश्त करने में खासी दिक्कत आती है।  हर समय एयर कंडीशनर या कूलर में रहना और खराब खानपान की आदत से इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में हर मौसम को झेलने या इसमें बीमार पड़ जाने का डर बना रहता है।

इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किन आयुर्वेदिक तरीकों को अभी से अपनाकर आने वाले गर्मी के दिनों में भी खुद को हेल्दी रख सकते हैं।  चलिए आपको बताते हैं इन आसान तरीकों के बारे में...।

## गर्मी में खुद को कैसे रखें ठीक

आयुर्वेद कहता है कि खुद को ठीक रखने के लिए शरीर के तीनों दोष वात, कफ और पित्त को संतुलित रखना जरूरी है।  अगर इनमें से एक भी दोष बिगड़ा हुआ है तो शरीर हर मौसम में परेशान रहता है।  गर्मी में पित्त दोष का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि भीषण गर्मी में पेट की समस्याएं ज्यादा होती हैं।  बिगड़ा पाचन अगर लगातार रहे तो उल्टी, दस्त, अपच, गैस या एसिटिडी की समस्या होने लगती है।

## गर्मी से बचने के लिए करें ये 3 उपाय

### बॉडी को रखें हाइड्रेट

जयपुर की आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ।  किरण गुप्ता कहती हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत हाइड्रेशन के साथ करनी चाहिए।  अगर हाइड्रेशन सही न हो तो सुबह उठते ही एक तरह का स्ट्रेस होता है।  मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुना पानी पिएं जिसमें थोड़ा सा नींबू और चुटकीभर हल्दी डालना न भूलें।  ये आपके दिन की बेहतर शुरुआत के लिए बेस्ट है। आप चाहे तो दिन की शुरुआत नारियल पानी से भी कर सकते हैं।

जयपुर की डाइटिशियन सुरभि पारीक कहती हैं कि जिन्हें एसिडिटी रहती है उन्हें खाली पेट नारियल पानी नहीं पीना चाहिए।  ऐसे में ये और प्रॉब्लम कर सकता है।  लेकिन गर्मी में

हाइड्रेशन को ठीक रखना है तो एक बार नारियल पानी जरूर पिएं।

### हल्की चीजें खाने की डालें आदत

एक्सपर्ट कहती हैं कि हमारा गर्मी में खानपान हल्का ही होना चाहिए।  ऐसे चीजों को खाएं जो सीजनल हो और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए।  आयुर्वेद कहता है कि ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हीट के साथ नेचुरली एलाइन हो जाए। गर्मी में मसालेदार या ज्यादा तला-भुना खाने की भूल न करें। आयुर्वेद के हिसाब से ये पेट में गर्मी को बढ़ाकर एसिटिडी या सीने में जलन की शिकायत कर सकते हैं।  मूंग जैसी ठंडी दाल का सेवन करें क्योंकि ये पेट के लिए वरदान से कम नहीं है।

### ब्रीदिंग प्रेक्टिस करें

गर्मी हो या सर्दी... हमें रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए।  इसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस की जाती है और ये हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।  इस प्रैक्टिस से न सिर्फ फिजिकल हेल्थ में सुधार आता है बल्कि मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त होती है।  एक्सपर्ट्स के मुताबिक शीतली और शीतकरी प्रणायाम हमारी बॉडी के सिस्टम को ठंडा रखती है।

इसके अलावा अणुलोम-विलोम बैलेंस बनाए रखता है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए रोजाना बालासन भी आप कर सकते हैं।  रोजाना 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचा सकती है।

# रोजाना सुबह एक गिलास नींबू पानी पीने से मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख फायदे

नींबू में विटामिन-सी के साथ एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन क्रिया को बेहतर करने से लेकर वजन कम करने तक में लाभदायक है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि नींबू का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है? आइए जानते हैं कि रोजाना सुबह एक गिलास नींबू पानी पीने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

### पाचन क्रिया को कर सकता है बेहतर

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू के पानी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में गैसट्रिक एंजाइम के उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर पाचन क्रिया को सुचारू रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस निचोड़कर पिएं। इससे पाचन को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

### रोग प्रतिरोधक क्षमता को दे सकता है बढ़ावा

नींबू में भरपूर विटामिन-सी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू में सूजन कम करने वाले और बैक्टीरिया को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। नींबू के पानी में विटामिन-सी की मात्रा बढ़ाने के लिए इसे बनाने के लिए ताजे और कसे हुए नींबू का उपयोग करें। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में सहायक हो सकता है।

### वजन को नियंत्रित करने में है कारगर

नींबू के पानी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स के साथ वजन घटाने वाले गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर में चर्बी के संचय को रोककर मोटापे को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही नींबू का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पाचन क्रिया को बेहतर कर सकता है, जो वजन नियंत्रित करने में सहायक है। इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।

### लिवर को साफ करने में है मददगार

नींबू का पानी लिवर को साफ करने में मदद कर सकता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करके लिवर को साफ करने में सहायक है। नींबू के पानी में एक खास एसिड पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। यह लिवर को साफ करने में सहायक हो सकता है।

### सांसों की बदबू कर सकता है दूर

नींबू के पानी में बैक्टीरिया को खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करके सांसों की बदबू दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू के पानी में मौजूद साइट्रिक एसिड लार के उत्पादन को बढ़ावा देकर दांतों पर प्लाक बनने से रोक सकता है। लाभ के लिए रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस निचोड़कर पिएं। यह सांसों की बदबू दूर करने में सहायक हो सकता है।

# खाड़ी देशों के युद्ध ने बढ़ाई टेंशन, बुखार से लेकर कैंसर तक की दवाएं होने वाली हैं महंगी!

खाड़ी देशों में भड़की जंग का सीधा असर अब आपके मेडिकल बिल पर पड़ने वाला है। वहां से आने वाले कच्चे माल की सप्लाई बाधित होने के कारण, देश में बुखार, एंटीबायोटिक से लेकर कैंसर तक की जरूरी दवाएं 10 से 20 फीसदी तक महंगी हो सकती हैं। फार्मा कंपनियों के लिए पुरानी कीमतों पर दवा बनाना मुश्किल हो गया है।

सरकार कैंसर के इलाज में काम आने वाली जीवनरक्षक दवाओं से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले एंटीबायोटिक और इंजेक्शन तक की कीमतों में 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के कारण दवा बनाने की लागत अचानक बढ़ गई है, जिसके चलते सरकार को सप्लाई बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है।

दरअसल, दवाएं बनाने की प्रक्रिया में 'सॉल्वेंट' (Solvents) नाम के खास तरह के रसायनों का इस्तेमाल होता है। दवाओं को घोलने और शुद्ध करने के काम आने वाले ये सॉल्वेंट कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन से जुड़े होते हैं, जो मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। वहां चल रही उथल-पुथल के कारण इन रसायनों की भारी कमी हो गई है।

हालांकि, ये केमिकल अंतिम दवा के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया इनके बिना पूरी नहीं हो सकती। सुरक्षा कारणों से दवा कंपनियां इनका बहुत बड़ा स्टॉक भी जमा करके नहीं रख सकतीं। ऐसे में अगर यह संकट दो-तीन महीने और चला, तो बाजार में कई जरूरी दवाओं की किल्लत हो सकती है।

### क्या दवाओं के दाम हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे?

राहत की बात यह है कि सरकार दवाओं के दाम हमेशा के लिए नहीं बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ एक शॉर्ट-टर्म या अस्थायी व्यवस्था होगी। सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है कि कीमतों में यह 10-20 प्रतिशत का इजाफा कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए किया जाए। जैसे ही वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन सामान्य होगी और रसायनों की आवाजाही ठीक होगी, दवाओं की कीमतें वापस अपने पुराने स्तर पर आ जाएंगी। अधिकारी इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वे फार्मा इंडस्ट्री की मदद जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को लंबे समय तक महंगाई के बोझ तले नहीं रखा जाएगा।

### फार्मा कंपनियों की मजबूरी या मुनाफा?

इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA) और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (OPPI) जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों ने सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। दवा बनाने वाली कंपनियों की दलील है कि लागत में हो रही इस बेतहाशा वृद्धि को अब वे खुद नहीं झेल सकतीं क्योंकि उनका मुनाफा पहले ही काफी कम हो चुका है। उनका तर्क है कि अगर कीमतों में राहत नहीं मिली, तो कुछ जरूरी दवाओं का उत्पादन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन जाएगा और उन्हें मजबूरन प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। इंडस्ट्री के एक धड़े ने तो 50 फीसदी तक दाम बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 10 से 20 फीसदी के कैलिब्रेटेड (संतुलित) दायरे से ज्यादा की बढ़ोतरी की मंजूरी किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी।

### पुराने और नए स्टॉक को लेकर फंसा पेंच

इस पूरी प्रक्रिया में एक तकनीकी पेंच भी फंसा हुआ है। अगर महंगी लागत में बनी दवाओं का उत्पादन इस संकट काल में होता है, तो हालात सामान्य होने के बाद कंपनियों के पास बचे हुए उस महंगे स्टॉक को किस रेट पर बेचा जाएगा? सरकार अभी इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाली इन जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने के लिए सरकार उन विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकती है, जो जनहित में असाधारण परिस्थितियों में लागू होते हैं। जल्द ही सरकार के भीतर चल रहा यह मंथन पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। सरकार की कोशिश यही है कि आम जनता के हितों की रक्षा भी हो और बाजार में जरूरी दवाओं की कोई कमी भी न आए।

# दुनिया में भारत का जलवा! चीन जमकर खरीद रहा हिंदुस्तानी सामान, अमेरिका को पीछे छोड़कर बना नंबर-1

दुनिया भर के बाजारों में इन दिनों भारत का डंका बज रहा है। आज हर बड़ा देश भारत के साथ कारोबार करने के लिए कतार में खड़ा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नई छलांग लगाई है। अब अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साथी बन गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि चीन के बाजारों में भारतीय सामानों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े देश अब भारत के बनाए उत्पादों पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा जता रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से भारत ने अपने देश में चीजें बनाने और उन्हें विदेशों में बेचने पर बहुत जोर दिया है। अब इस मेहनत का शानदार असर दिखने लगा है। नए वित्तीय वर्ष (2025-26) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत और चीन के बीच कुल 151।1 अरब डॉलर का बड़ा कारोबार हुआ है। इसमें सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि हमने चीन को जो सामान बेचा है (निर्यात), उसमें लगभग 37 फीसदी (36।66%) का जबरदस्त उछाल आया है। भारत ने चीन को 19।47 अरब डॉलर का सामान भेजा है। चीन के लोग और वहां की कंपनियां हिंदुस्तानी सामानों को हाथों-हाथ ले रही हैं।

### फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, इसलिए हम भी कर रहे खरीदारी

जब कोई देश तेजी से तरक्की करता है, तो उसे नई फैक्ट्रियां लगाने और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए बहुत सारे कच्चे माल और मशीनों की जरूरत पड़ती है। भारत भी इस समय इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत ने भी चीन से काफी सामान खरीदा है। हमने चीन से 131।63 अरब डॉलर की खरीदारी की है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अपने देश में विकास को और तेज करने के लिए जरूरी तकनीक और कच्चा माल जुटा रहा है। हम विदेशों से मशीनें लाकर अपने देश में ही और ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारी मजबूत होती अर्थव्यवस्था की निशानी है।

### अमेरिका के साथ भारत का शानदार मुनाफा

भारत का व्यापार सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के साथ भी हम बहुत फायदे में हैं। आसान भाषा में समझें तो हम अमेरिका से सामान खरीदते कम हैं और उन्हें अपना सामान बेचते ज्यादा हैं। इसी वजह से हम अमेरिका के साथ 34।4 अरब डॉलर के भारी-भरकम मुनाफे में हैं। भारत ने अमेरिका को 87।3 अरब डॉलर का सामान बेचा है। यह दिखाता है कि अमेरिका जैसे अमीर देश को भी भारत की आईटी सेवाओं, दवाओं और दूसरे उत्पादों की कितनी ज्यादा जरूरत है। हमारी यह साझेदारी दुनिया में हमारी अहमियत को और बढ़ा रही है।

### दुनिया के कई और देशों में भी भारत की धाक

भारतीय कारोबारी अब सिर्फ गिने-चुने देशों तक रुकने वाले नहीं हैं। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि हमारा सामान दुनिया के कोने-कोने में पहुंच रहा है। यूएई, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे अमीर देशों से लेकर ब्राजील, नेपाल और वियतनाम जैसे उभरते हुए बाजारों में भी भारत अपना सामान भेज रहा है। इन सभी देशों में हमारे उत्पादों की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

# इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर हेलीकॉप्टर क्रैश, आठ की मौत; राहत-बचाव कार्य जारी

जकार्ता। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पाम ऑयल के बागानों के बीच उड़ान भर रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।

यह हेलीकॉप्टर 'पीटी मैथ्यू एयर नुसंतारा' कंपनी का था और इसका मॉडल एयरबस H130 था। गुरुवार को इसने पश्चिमी कालीमंतन प्रांत के मेल्वी जिले से उड़ान भरी थी। इसे कुबू राया जिले में स्थित एक दूसरे पाम ऑयल बागान तक जाना था। लेकिन उड़ान भरने के महज पांच मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया।

हादसे खबर मिलते ही खोज अभियान शुरू किया गया। नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी और परिवहन मंत्रालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर का मलबा सेकादौ जिले के घने जंगलों में मिला है। बचाव दल ने वहां से दो क्रू सदस्यों और छह यात्रियों के शव बरामद किए हैं। मरने वालों में एक व्यक्ति मलेशिया का नागरिक था।

इंडोनेशिया लगभग 27 करोड़ की आबादी वाला देश है। यह देश अक्सर विमान, हेलीकॉप्टर और नाव डूबने सहित ट्रांसपोर्टेशन दुर्घटनाओं से परेशान रहा है। परिवहन सुरक्षा को लेकर यहां पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस हादसे की जांच कर रहे हैं।

# अमेरिकी नीति पर ट्रंप के बड़े बयान, ईरान से समझौते के लिए खुद जाएंगे पाक! पीएम मोदी पर भी बोले

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 40 दिनों से अधिक की जंग के बाद तनावपूर्ण शांति के बीच आई इस टिप्पणी को उनके यू-टर्न की तरह भी पेश किया जा रहा है।

इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी टिप्पणी की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'दोस्त' बताते हुए कहा, मोदी के साथ फोन पर उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी' रही। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के फोन कॉल की पुष्टि की थी।

गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी

दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को सकारात्मक बताया। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं।

### 10वां युद्ध रुकवाने का दावा

राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और ईरान से इतर इस्राइल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर भी बयान दिया। उन्होंने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 10वां युद्ध रोकने में सफलता हासिल की है।

### ट्रंप का दावा- ईरान की नौसेना नष्ट, बहुत जल्द मिलेगी जीत

वहीं ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ बहुत जल्द जीत का दावा किया। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं में भारी गिरावट का उल्लेख किया। ट्रंप ने ईरान को 'कठिन, स्मार्ट देश' बताया, पर कहा उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। ट्रंप ने ईरानी कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने सुलेमानी को 'सबसे बुरे आतंकवादियों में से एक' बताया, उस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमलों का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम विस्तार पर अनिश्चितता जताई। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जल्द ही एक समझौता हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना मुख्य लक्ष्य है। अगले दौर की वार्ता सप्ताहांत में होने की संभावना है।

### ट्रंप की नीतियों के लिए डोनरो डॉक्ट्रिन शब्द क्यों?

डोनरो सिद्धांत जुमले का इस्तेमाल ट्रंप की 2026 की विदेश नीति के संदर्भ में किया जाता है। इस धारा के तहत सरकार 'अमेरिका सबसे पहले और केवल अमेरिका' जैसे रुख पर जोर देती है। डोनरो सिद्धांत पूर्व राष्ट्रपति के दौर में इस्तेमाल 'मोनरो सिद्धांत' से प्रेरित है। दरअसल, 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने यूरोपीय उपनिवेशीकरण बंद करने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में किसी भी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने जैसे कृत्य के रूप में देखा जाएगा। बीते करीब 200 साल से अधिक समय से इस नीति को डोनरो सिद्धांत की तरह पेश किया जा रहा है।

# पैसे की ताकत दिखा रहे मस्क: रिकॉर्ड बनाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या है स्पेसएक्स की योजना?

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने अमेरिकी शेयर बाजार NASDAQ में लिस्टिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ से पहले गोपनीय दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, स्पेसएक्स करीब दो ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन को लक्ष्य बनाते हुए बाजार में उतर सकती है। कंपनी अपने कुल हिस्सेदारी का केवल छोटा भाग बेचकर लगभग 75 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह सौदा सफल रहा तो यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है।

### कंपनी का सफर और बिजनेस मॉडल

2002 में स्थापित स्पेसएक्स का लक्ष्य मानवता को बहुग्रह बनाना है। कंपनी ने रॉकेट और लॉन्च व्हीकल के दोबारा उपयोग की तकनीक विकसित कर अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत को नाटकीय रूप से कम किया है, जो 2000 के दशक की शुरुआत की तुलना में महज 5% तक रह गई है। कंपनी अब तक करीब 600 सफल रॉकेट लैंडिंग कर चुकी है, जिससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को नया आयाम मिला है। हालांकि, स्पेसएक्स की कमाई का बड़ा हिस्सा उसके सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस स्टारलिंक से आता है, जो दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक यूजर्स को सेवा दे रहा है।

### एक्स एआई के साथ ऐतिहासिक विलय

फरवरी 2026 में स्पेसएक्स ने xAI के साथ विलय किया, जो ग्रोक का डेवलपर है। यह अब तक का सबसे बड़ा निजी कॉरपोरेट विलय माना जा रहा है। इस सौदे में xAI का मूल्य 250 अरब डॉलर और स्पेसएक्स का एक ट्रिलियन डॉलर आंका गया, जिससे संयुक्त इकाई का मूल्य 1.25 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इस विलय ने स्पेसएक्स के आईपीओ की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है।

### आईपीओ की रणनीति और उपयोग

मस्क के मुताबिक, आईपीओ से जुटाई गई रकम का उपयोग अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर सैटेलाइट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है, जिससे पृथ्वी पर बिजली और पानी जैसी सीमाओं से बचा जा सके।

### नियमों में बदलाव और बाजार पर असर

स्पेसएक्स की संभावित लिस्टिंग को देखते हुए NASDAQ ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। आमतौर पर किसी कंपनी को इंडेक्स में शामिल होने के लिए कम से कम 10% शेयर बाजार में उपलब्ध होना जरूरी होता है, लेकिन स्पेसएक्स के मामले में इस शर्त में ढील दी गई है। साथ ही, नई लिस्टेड कंपनियों के लिए इंडेक्स में शामिल होने की समय सीमा भी तीन महीने से घटाकर 15 ट्रेडिंग दिन कर दी गई है। इससे स्पेसएक्स जल्दी ही NASDAQ 100 जैसे प्रमुख इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा, जो इंडेक्स फंड या ईटीएफ में निवेश करते हैं। अनुमान है कि NASDAQ 100 को ट्रैक करने वाले फंड्स में 600 अरब डॉलर से अधिक की रकम लगी हुई है, जो स्पेसएक्स के शामिल होते ही अपने-आप उसमें निवेश करेगी।

### वैल्यूएशन पर उठ रहे सवाल

हालांकि, स्पेसएक्स की ऊंची वैल्यूएशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कंपनी का पिछले साल का राजस्व करीब 15 अरब डॉलर रहा, जबकि दो ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के हिसाब से यह बहुत अधिक मूल्यांकन माना जा रहा है। तुलना करें तो टेस्ला जैसी महंगी कंपनी के मुकाबले भी स्पेसएक्स का वैल्यूएशन कई गुना ज्यादा आंका जा रहा है।

### निवेशकों के लिए क्या मायने?

स्पेसएक्स ने संकेत दिया है कि वह अपने शेयरों का करीब 30% हिस्सा रिटेल निवेशकों को भी उपलब्ध कराना चाहती है। मस्क की कंपनियां पहले से ही आम निवेशकों के बीच लोकप्रिय रही हैं, ऐसे में इस आईपीओ को लेकर भी भारी उत्साह की संभावना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी ऊंची वैल्यूएशन और नियमों में ढील के बीच निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े निवेशकों और कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और जोखिम भी ज्यादा हो सकता है।

# जनसंख्या कंट्रोल करने में जो राज्य फेल रहे उन्हें दिया जा रहा राजनीतिक इनाम... परिसीमन पर संसद में बोले थरूर

**नई दिल्ली, एजेंसी।** संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर चर्चा लगातार दूसरे दिन भी जारी है। परिसीमन की कोशिश का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण करने में नाकाम रहे उन्हें राजनीतिक इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए।

लोकसभा में चल विशेष सत्र के दूसरे दिन चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस नेता थरूर ने कहा, "सरकार ने नोटबंदी के दौरान जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई थी, वैसी ही जल्दबाजी परिसीमन की प्रक्रिया में भी दिखाई जा रही है, और यह एक तरह का 'राजनीतिक विमुद्रीकरण' है। परिसीमन के मुद्दे की वजह से महिलाओं के आरक्षण को बंधक बना लिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

### परिसीमन बिल को लेकर थोड़ा इंतजार करें : थरूर

शशि थरूर ने अमित शाह के फॉर्मूले को लेकर कहा, "अमित शाह द्वारा सुझाया गया 50 फीसदी का फ़ॉर्मूला एक जोखिम भरा राजनीतिक बयान है। यह विधायिका द्वारा किया गया कोई वादा नहीं है।" लोकसभा की सीट 850 तक किए जाने की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, "लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने से यह एक ऐसी संस्था बन जाएगी जो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। लोकसभा का आकार तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा का आकार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे दोनों सदनों के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन परिसीमन बिल के मामले में हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

### परिसीमन को लेकर 3 बातों का ध्यान रखें : थरूर

परिसीमन से होने वाले नुकसान और इसके लिए 3 चीजों पर गौर करने की बात करते हुए थरूर ने आगे कहा, "हमें इस बारे में साफ-साफ बात करनी चाहिए कि परिसीमन के क्या नतीजे हो सकते हैं। परिसीमन के लिए गहन विचार-विमर्श की जरूरत होती है। लेकिन इसमें 3 अहम टकराव के बिंदु हैं, पहला, छोटे और बड़े राज्यों के बीच संतुलन। दूसरा, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के बीच संतुलन, जिन्होंने अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति लागू किए; जबकि उत्तरी राज्यों के बीच संतुलन, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। परिसीमन में, जो राज्य जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में नाकाम हो गए हैं, उन्हें अब ज्यादा राजनीतिक ताकत देकर पुरस्कृत किया जाएगा। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम यही संदेश देना चाहते हैं। तीसरा, उन राज्यों के बीच संतुलन जो हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन रहे हैं, और उन राज्यों के बीच जो केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड के मुख्य प्राप्तकर्ता हैं।" दूसरी ओर, बहस में शामिल होते हुए DMK की सांसद कनिमोझी ने गुरुवार रात 10 बजे महिला आरक्षण बिल को नोटिफाई करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। कनिमोझी ने कहा कि सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया। सदन में हम सभी सांसद लगातार चर्चा कर रहे हैं और सरकार ने इस बिल को नोटिफाई कर दिया। इससे यही समझ आता है कि सत्ता में मौजूद लोगों के अंदर सदन के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

# सहमति से बने संबंध वाले पॉक्सो केस रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी की ये गाइडलाइंस

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पॉक्सो एक्ट में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें रिश्ते लड़का और लड़की की सहमति से बने होने की बात कही जाती है। इसके बारे में लड़की की तरफ से खुद स्पष्टता दी जाती है। लड़की कानूनी लड़ाई न लड़ने की अपील करती है क्योंकि उस मामले में दोनों की शादी की जा चुकी होती है, लेकिन चूंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम होती है, ऐसे में उसे de-jure victim यानी कानूनी रूप से पीड़िता मान लिया जाता है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामलों को कब रद्द किया जा सकता है, इसको लेकर कई सिद्धांत निश्चित किए गए। जस्टिस अनुप जैराम भांभानी ने इससे जुड़ा अहम फैसला दिया है।

कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना कानून के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसी परिस्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत सावधानी और संवेदनशीलता से समझने और विचार करने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत किसी अपराध को रद्द करने की याचिका पर विचार किया जाता है तो कोर्ट को उन कारणों का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर क्यों पीड़िता यह मानने से इनकार कर रही है। उसे कोई नुकसान या चोट पहुंची है। क्या वो किसी के दबाव में तो ऐसा नहीं कर रही है। कोर्ट को इस बात पर अपनी संतुष्टि भी दर्ज करनी चाहिए। ये चीजें उन मामलों पर होंगी जो कानूनी तौर पर पीड़ित की सहमति पर आधारित होती हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को उन अपराधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो अपने पक्ष में आपराधिक कार्यवाही रद्द करवाने के लिए धोखे, चालबाजी या बेईमानी के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत आने वाले अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए, सहमति के संबंध में मजबूत सुरक्षा उपाय और नियम तय करना जरूरी है।

जज ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने पर 'कोई आपत्ति नहीं' (no-objection) देते समय, पीड़ित (de-jure victim) सचमुच अपनी मर्जी और इच्छा से काम कर रही है। उसे ऐसी आपत्ति न देने के लिए गुमराह, दबाव में या धोखे में तो नहीं डाला गया है। कोर्ट ने यहा भी साफ किया है कि अगर लड़की और लड़के के बीच समझौता या शादी हो जाती है तो अदालत को ये देखना होगा कि ये समझौता वाकई में सच्चा है या फिर केस और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया गया है।

### इन चीजों पर भी गौर करना जरूरी

क्या दोनों पक्ष लंबे समय से एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं?

क्या दोनों पक्षों के बच्चे हैं, जिनका भविष्य भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने के फैसले से प्रभावित होगा?

क्या अपराधी पर पीड़िता के साथ किसी भी तरह की हिंसा या क्रूरता करने का आरोप है?

संबंधित समय पर अपराधी और कथित पीड़ित की उम्र क्या थी?

# नेहा धूपिया की हॉलीवुड में दस्तक, फिल्म 52 ब्लू से सामने आई पहली झलक

अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी अपकमिंग फिल्म 52 ब्लू को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म से वह हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसका पहला लुक और ट्रेलर जारी किया है। नेहा धूपिया इसमें एक अलग लुक में नजर आ रही हैं। यह फिल्म फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बैकग्राउंड में एक भारतीय प्रवासी मजदूर की जिंदगी पर आधारित है। 2 मिनट 11 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नेहा धूपिया ने उस व्यक्ति (यादव शशिधर) की मां का किरदार निभाया है, जो लियोनेल मेस्सी का बहुत बड़ा फैन है। वो लियोनेल मेस्सी से मिलने विदेश जाता है। वहां जाकर वह फंस जाता हैं। भारत में आशीष का परिवार पहले तो उनके विदेश जाने पर खुश होता है, बाद में जब वह वापस नहीं आता है, तो परिवार के लोग परेशान होते हैं। बेटे के दूर हो जाने पर नेहा धूपिया भी परेशान होती हैं।

इस फिल्म में नेहा धूपिया पहली बार एक मां का किरदार निभाएंगी। उनके साथ आदिल हुसैन भी हैं, जो उनके पति का किरदार निभा रहे हैं। यह इन दोनों की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कोच्चि में फिल्माया गया है, जहां के तटीय और द्वीपीय नजारे कहानी को बेहतर तरीके से पेश करते हैं। यह फिल्म मिस्र के फिल्ममेकर अली अल-अरबी के निर्देशन में बनी है।

आपको बता दें कि नेहा धूपिया ने 2003 में फिल्म कयामत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आखिरी बार वह फिल्म बैड न्यूज 2024 में नजर आई थीं। अब वह हॉलीवुड फिल्म 52 ब्लू में नजर आएंगी।

# रामायण पार्ट 1 में राम-रावण अवतार में क्या आमने-सामने होंगे रणबीर कपूर और यश?, साउथ सुपरस्टार ने दिया हिंट

अभिनेता यश ने रामायण में रावण की अपनी भूमिका के बारे में कुछ नई जानकारी साझा की है, और एक खुलासे ने प्रशंसकों को चौंका दिया है। अभिनेता ने पुष्टि की कि दो फिल्मों की महाकाव्य सीरीज के पहले भाग में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले रणबीर कपूर के साथ उनके कोई सीन नहीं हैं। यह खुलासा फिल्म की भव्य रिलीज से पहले बढ़ती उत्सुकता के बीच आया है।

दोनों किरदारों के बीच के संबंध के बारे में बात करते हुए यश ने बताया कि कहानी की मेकिंग के कारण पहले भाग में दोनों अलग-अलग नजर आते हैं। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में हम दोनों कभी भी एक साथ स्क्रीन पर नहीं आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दो भागों वाली फिल्म है, इसलिए पहले भाग में रावण के रूप में मेरा अपना राज्य है और राम का अपना। उन्होंने आगे बताया कि दोनों किरदारों का आमना-सामना केवल दूसरे भाग में होगा, जो अगले साल रिलीज़ होने वाली है।

स्क्रीन स्पेस साझा न करने के बावजूद, यश ने रणबीर के बारे में गर्मजोशी से बात की और उनके काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हम असल जिंदगी में कुछ बार मिले हैं, और वह एक शानदार अभिनेता हैं। मुझे लगता है कि यह आपसी सम्मान का नतीजा है।

उन्होंने आगे कहा कि पूरी टीम कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश करने पर केंद्रित हैः जब आप रामायण जैसी महत्वाकांक्षी और असाधारण चीज करने निकलते हैं, तो हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना बेस्ट दें। हमारी सोच एक जैसी है, इसलिए हमारे बीच तालमेल की कोई समस्या ही नहीं है। यश ने रावण का किरदार निभाने के अपने फैसले और इस चरित्र के पीछे के दर्शन के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म केवल अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है।

उन्होंने कहा, रामायण की कहानी सिर्फ अच्छे या बुरे व्यक्ति के बारे में नहीं है। आप हर चीज में बेस्ट हो सकते हैं। आपके पास सभी बेहतरीन कौशल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका निर्णय मायने रखता है।

अभिनेता ने समझाया कि रावण एक व्यक्तित्व है जो उसके कर्मों से बनता है। उन्होंने आगे कहा, आप सब कुछ जानते हैं। आप संगीत में अच्छे हैं। आप शास्त्रों में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्म, आपके कर्म ही आपको परिभाषित करते हैं। इसी नजरिए से मैंने इस किरदार को निभाया।

उन्होंने कहा, हम इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, ये हमारी संस्कृति और बिलीव सिस्टम का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एंगल है, हर किरदार का अपना नजरिया होता है और ज्यादातर समय वे जो कर रहे होते हैं उस पर विश्वास करते हैं।

रामायण भी चर्चा का मुख्य विषय रही है। यह फिल्म दो भागों में निर्मित एक विशाल बजट और व्यापक तकनीकी उपयोग के साथ बनाई जा रही है। यश ने इस परियोजना को महत्वाकांक्षी बताया और कहा कि इसमें शामिल सभी लोग कहानी को भव्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत हैं। पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा।

# फोर्स 3 से जॉन अब्राहम की वापसी, हर्षवर्धन राणे भी साथ; धमाकेदार एक्शन से थिएटर में मचेगा तहलका, रिलीज डेट से उठा पर्दा

एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉन अब्राहम की मशहूर फ्रेंचाइजी फोर्स की तीसरी कड़ी यानी फोर्स 3 पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू हो गया है और पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह समर्पित नजर आ रही है। इस फ्रैंचाइजी के पिछले दो भागों की सफलता को देखते हुए दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इस बार फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ हर्षवर्धन राणे भी नजर आने वाले हैं, इसका मतलब है कि स्वैग डबल होगा।

फोर्स 3 में इस बार दर्शकों को कुछ पुराने चेहरों के साथ-साथ नई प्रतिभाएं भी देखने को मिलेंगी। फिल्म में जॉन अब्राहम एक बार फिर एसीपी यशवर्धन सिंह के अपने कड़क अवतार में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ इस बार हर्षवर्धन राणे और तान्या मानिकतला मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। हर्षवर्धन के किरदार को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, जबकि तान्या को इससे पहले ए सूटेबल बॉय में काफी पसंद किया गया था।

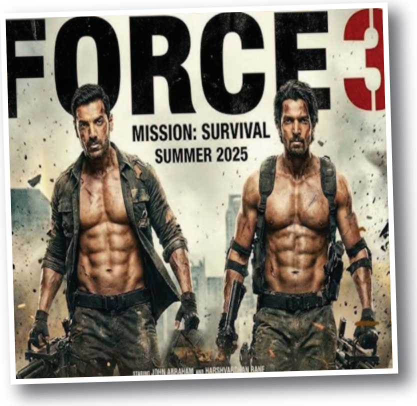


निर्देशन की जिम्मेदारी भाव धुलिया को सौंपी गई है, जो खाकीः द बिहार चैप्टर और द फ्रीलांसर जैसी सफल सीरीज के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाव धुलिया ने इस फ्रैंचाइजी के पहले भाग में दिवंगत निर्देशक निशिकांत कामत के साथ बतौर सहायक काम किया था, इसलिए उनके लिए यह एक घर वापसी जैसा अनुभव है।

फिल्म के निर्माण और अभिनय पर बात करते हुए जॉन अब्राहम ने कहा कि फोर्स एक ऐसी फ्रैंचाइज़ी है जिस पर उन्हें हमेशा से गहरा विश्वास रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार फिल्म के स्तर को और भी बड़ा बनाया जा रहा है। जॉन ने हर्षवर्धन राणे की भी तारीफ की और कहा कि वे उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में पेश करने के लिए उत्साहित हैं। वहीं निर्माता शील कुमार ने जॉन अब्राहम के साथ अपने लंबे रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि फोर्स 3 उनके लिए भरोसे और साझा विजन का परिणाम है। निर्देशक भाव धुलिया ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तभी वे इसके दीवाने हो गए थे और अब वे इसे पर्दे पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

हर्षवर्धन राणे ने इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जॉन अब्राहम जैसे दिग्गज और भाव धुलिया के विजन के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात है। तान्या मानिकतला भी इस एक्शन फ्रैंचाइजी से जुड़कर काफी उत्साहित हैं और उन्होंने अपनी भूमिका को विशेष बताया है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म की पटकथा सिमाब हाशमी ने लिखी है, संगीत रवि बसरूर का है और बोल इरशाद कामिल ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण जॉन अब्राहम की जेए एंटरटेनमेंट और शील कुमार की कैरोलिना कॉर्पोरेशन के बैनर तले हो रहा है। फोर्स 3 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com